छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 57 ■ अम्बिकापुर, बुधवार 18 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जनजातीय समाज का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की

■ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को दी गई स्वीकृति

बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर दिया जोर

छ.ग.फ्रंटलाइन बैकुंठपुर। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार ने सरगुजा और बस्तर के विकास पर अपना मुख्य फोकस रखा है। प्राधिकरण गठन के साथ महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र को विकास से जोड़ा जा रहा है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के माध्यम से सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और क्षेत्र की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से सरगुजा क्षेत्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री एवं सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक बैकुंठपुर जिला पंचायत के मंथन सभाकक्ष में संपन्न हुई, जिसमें सरगुजा संभाग के जिलों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई तथा विभिन्न चल रहे कार्यों की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 543 विकास कार्यों के लिए 4905.58 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 606 कार्यों को भी औपचारिक अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत सभी कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए तथा लंबित कार्यों को मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की पूर्व बैठक के पालन-प्रतिवेदन के संबंध में बताया गया कि पर्यटन विकास को भी प्रमुखता दी गई है। जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप को क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 40 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा 5 फरवरी 2026 को इन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन संपन्न किया जा चुका है, जिसके बाद अब तेजी से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं।

बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं के अनुबंध निरस्त किए गए हैं तथा एक मुख्य अभियंता और आठ कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि जंगली हाथियों के हमलों से प्रभावित लोगों की सहायता के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मकान क्षति की क्षतिपूर्ति राशि को 18 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार बढ़ा दिया गया है, जबकि अन्य मुआवजा मदों की दरों में वृद्धि के लिए विभागीय परीक्षण जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी-द्वंद्व प्रभावित परिवारों को त्वरित और पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा राशि में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों के सुझाव और शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सुझाव के साथ शिकायतें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राप्त सुझाव और शिकायतों का परीक्षण करने तथा इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की बात कही। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने वनांचल क्षेत्रों में विद्युतीकरण, हाथी-प्रभावित क्षेत्रों में हाथी-विचरण के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने, हाथी से फसलों एवं संपत्ति को हुए नुकसान पर मुआवजा राशि बढ़ाने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य अपूर्ण होने, जल स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराने, ग्रामीण सड़कों में भारी वाहन संचालित होने से सड़क को नुकसान होने, लुंड्रा, बतौली, प्रतापपुर क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन बढ़ने के कारण गन्ना मिल प्रारंभ करने, मजदूरों के लंबित भुगतान करने, त्रुटिपूर्ण बिजली बिलों को सुधारने के संबंध में सुझाव दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने हाथी आदि से हुए नुकसान पर मुआवजा राशि बढ़ाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने, हाथी-प्रभावित क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर लाइट लगाने, गन्ना मिल को प्रारंभ करने और गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं को दूर करने, उन्हें मजदूरी भुगतान करने, बिजली उपभोक्ताओं के बिल संबंधी त्रुटियों को दूर करने की दिशा में कार्यवाही प्रचलित होने और आने वाले दिनों में बड़ा निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण, बिजली तार बिछाकर मछली मारने, वन्यजीव सहित मानव को नुकसान पहुँचाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही।

प्राधिकरण की बैठक में विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सोनहत विकासखंड के गांवों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। वहीं, जशपुर जिले में अत्यधिक बिजली बिलों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 568 त्रुटिपूर्ण बिलों का सुधार किया गया। इसके अतिरिक्त धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी हो सके। बैठक में प्राधिकरण मद से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर सहित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, जिससे विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों तक पहुँचे और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिल सके।

प्राधिकरण की बैठक से बढ़ रही है जिलों की पहचान: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में कहा कि सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक विगत वर्ष जशपुर जिले के मयाली में की गई थी। बैठक के पश्चात मयाली की पहचान पर्यटन केंद्र के रूप में होने लगी है। विश्व के बड़े शिवलिंग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला और स्वदेश दर्शन योजना के तहत 9 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। बैठक की सार्थकता रही कि मयाली की पहचान बढ़ गई है और बाहर के पर्यटक आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्राधिकरण की दूसरी बैठक बैकुंठपुर में हुई है। यहाँ पहली बार झुमका जलाशय को क्रूज के माध्यम से देखने का अवसर मिला। मंत्रीगण सहित सभी अधिकारी भी आए। यहाँ भी पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। इस तरह अलग-अलग जिलों में बैठक होने का लाभ जिले को मिलता है। इस दौरान जिले के कृषि एवं प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद चिंतामणी महराज, विधायक भइयालाल राजवाड़े, विधायकगण भूलन सिंह मरावी, प्रमोद मिंज, शकुंतला पोर्ते, श्रीमती बुद्धेश्वरी पैकरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव एस. बासव राजू, संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, सहित उपस्थित मंत्रियों, सांसद, विधायको तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह भेंट की।

नाबालिक किया स्टंटबाजी, न्यायालय ने 37 हजार अर्थदंड से किया दण्डित

खतरनाक तरीके से वाहन चालन के मामले में पुलिस ने एमजी हैक्टर वाहन किया था जब्त

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नाबालिक वाहन चालक की स्टंटबाजी वाहन मालिक को भारी पड़ी, पुलिस ने वाहन जप्त करके मामला न्यायालय के सुपुर्द किया था। न्यायालय ने वाहन स्वामी को 37 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। नाबालिक को अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने हेतु देने पर एमजी हैक्टर वाहन के मालिक के विरुद्ध इस्तगासा तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया था। थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक थाना गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि नावापारा मुख्य मार्ग में कुछ युवक एमजी हैक्टर वाहन में स्टंटबाजी करके खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे है। वाहन चालक अपने अन्य साथियों को वाहन में बाहर की ओर बैठाकर वाहन चलाते हुए सरेराह प्रदर्शन कर रहा है। मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना में प्रयुक्त वाहन एमजी हैक्टर क्रमांक सीजी 15 ईई 5665 को तलाशकर अपने कब्जे में लिया। अग्रिम विवेचना कार्रवाई में सामने आया कि वाहन चलाने वाला और उसके साथी नाबालिक हैं। ऐसे में पुलिस ने सभी के स्वजनों को थाना में तलब किया था। पुलिस के संदेश पर स्वजन थाना पहुंचे, इन्हें नाबालिक वाहन चालक के द्वारा अपने अन्य 02 नाबालिग साथियों को बिठाकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई। वाहन स्वामी ने धारा 133 एम.व्ही. एक्ट का नोटिस देने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया,

इस एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज

नाबालिक वाहन चालक द्वारा एमव्ही एक्ट की धारा 4/181 एवं 184, और वाहन स्वामी के द्वारा वाहन नाबालिग को अनाधिकृत रूप से प्रदाय करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 199 ए, 5/180 का अपराध घटित करना पाया गया। मौके पर प्रतिकर राशि प्रदाय नहीं करने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध ईस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया। मामले में वाहन मालिक जितेन्द्र सोनी पिता नंदू सोनी 32 वर्ष, निवासी मनेन्द्रगढ़ रोड पटपरिया, थाना गांधीनगर को न्यायालय से 37 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

इसके बाद एमजी हैक्टर वाहन को पुलिस टीम जप्त कर ली। सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष कुमार ठाकुर, आरक्षक रमन मण्डल, घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

इलाज में लापरवाही और बिना सूचना शव को मर्च्युरी में रखवाने पर मचा हंगामा

ट्रक की ठोकर से घायल महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़क हादसे में घायल महिला की शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध जिला अस्पताल मौत में हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन ने अस्पताल के डॉक्टरों पर समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। वहीं मौत के बाद शव को आननफानन में मर्च्युरी में रखने को लेकर भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार ज्योति मंडल पति विजय मंडल 28 वर्ष सूरजपुर जिला के जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम गणेशपुर की रहने वाली थी। ज्योति, मंगलवार की सुबह करीब 11 पति के साथ बाइक में सिलफिली बैंक जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 15 एडब्ल्यू 0406 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए इन्हें ठोकर मार दिया। हादसे में ज्योति मंडल सड़क पर फेंका गई थी, उसे सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई थी। स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए थे। यहां दो घंटे तक इलाज चलने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन ने चिकित्सक पर समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। महिला के मामा राजू मिर्धा का कहना है दुर्घटना के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया। यहां केवल एक इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद उसे न तो कोई डॉक्टर देखने आया और न ही स्टाफ नर्स। आरोप है कि कुछ देर बाद जब ज्योति को दो-तीन बार सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो इसकी जानकारी यहां के स्टाफ को दी गई, पर किसी ने ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। अंतत: महिला की मौत हो गई। इसके बाद कोहराम की स्थिति बन गई और आननफानन में शव को मर्च्युरी में भेजवा दिया गया। शव को गायब देखकर एक बार फिर क्षणिक हंगामा मचा, जिस पर पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवाने की जानकारी दी। स्वजन का कहना है कि उन्हें मृत्यु के बाद शव मुर्दाघर में ले जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई। इनका कहना है कि अगर समय पर इलाज व ऑक्सीजन की सुविधा दी गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। पुलिस की समझाइस के बाद स्वजन पोस्टमार्टम कराए, और शव लेकर अस्पताल से रवाना हुए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन मामले में लापरवाही नहीं मानते हुए मौत का अन्य कारण मान रहा है।

वन विभाग सोते रहा, शराब पीने के बाद चंदन का पेड़ काटकर ले गए तस्कर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में कलेक्टर बंगला रोड में स्थित हर्बल हाउस से चंदन का पेड़ काटकर ले जाने का मामला सामने आया है। करीब 25 फीट ऊंचा यह पेड़ वन विभाग के शासकीय क्वार्टर के बाहर लगा था। मौके को देखने के बाद प्रतीत होता है कि चंदन का पेड़ काटकर ले जाने के पहले चोर बैठकर शराब पिए, बाद में आरा मशीन से पेड़ को काट दिया। इसके पहले भी चंदन का पेड़ होने के कई मामले सामने आए हैं, इसके बाद भी वन विभाग बेशकीमती चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए कोई एहतियात बरतने जैसा कदम नहीं उठा पाया है। हैरत की बात यह है कि विशाल वृक्ष को काटकर चोरी करके ले जाने की घटना से वरिष्ठ अधिकारी दोपहर तक अनजान रहे। इसके पहले दिसंबर 2024 में अज्ञात तस्करों ने मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पीछे स्थित नर्सरी से तीन चंदन के पेड़ों को काटकर पार कर दिया था, एक को मौके पर ही छोड़ दिया था। देखा जाए तो वन विभाग के जहां आला अफसर बैठते हैं, वहां सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला एक तरह से सामने आया था। वहीं माखन विहार फॉर्म हाउस से भी करीब ढाई दशक पुराने चंदन के चार पेड़ों की चोरी हुई थी, जिसकी कीमत का आंकलन 8 लाख रुपये किया गया था। चोरी की इन घटनाओं में इलेक्ट्रॉनिक आरी का इस्तेमाल करने जैसी बातें भी सामने आई थी। सभी घटनाएं रात्रि के समय हुईं, लेकिन तस्करों का पता नहीं चल पाया। तस्कर पुन: चैलेंजिंग मोड में हर्बल हाउस से चंदन का कीमती पेड़ काटकर ले गए, इसकी भनक वन विभाग को नहीं लग पाई। लगातार चंदन के कीमती पेड़ों की चोरी होना और तस्करों का पकड़ में नहीं आना सवालों के घेरे में है।

प्लेस ऑफ सेफ्टी में गार्ड से मारपीट करके 13 अपचारी बालक भागे, 4 पकड़ाए

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) से सोमवार की रात हत्या, बलात्कार, मारपीट व चोरी के मामले में शामिल 13 अपचारी बालक फरार हो गए। इनके द्वारा ड्यूटी पर मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस इनके खोजबीन में जुटी और 4 अपचारी बालकों को कब्जे में ले ली है। समाचार लिखे जाने तक 9 बालकों की तलाश जारी है। बता दें कि विभिन्न अपराधों में शामिल अपचारी बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह के अलावा गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था में भी रखा जाता है। यहां वर्तमान में करीब दो दर्जन अपचारी बालकों को रखा गया था। सोमवार की रात करीब 9 बजे ड्यूटी पर मौजूद गार्डों के द्वारा अपचारी बालकों को परिसर से कमरे में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक 15 बालकों ने संभवत: सुनियोजित तरीके से दरवाजे को धक्का देकर गार्डों पर हमला कर दिया। गार्डों ने इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अपचारी बालक एक गार्ड के साथ मारपीट करने में लगे थे, जबकि दूसरे को कुछ लड़के पकड़ कर रखे थे। मारपीट के बाद पीछे के दरवाजे से सभी अपचारी बालक भागने में सफल हो गए। इसकी सूचना रात में ही संस्था प्रबंधन की ओर से गांधीनगर थाने में दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 4 अपचारी बालकों को कब्जे में लिया है, अन्य की तलाश जारी है। संस्था के कर्मचारी का कहना है कि फरार अपचारी बालकों के विरूद्ध हत्या, दुष्कर्म, चोरी व मारपीट के मामले दर्ज हैं। बहरहाल बड़ी संख्या में अपचारी बालकों के फरार होने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस फरार बालकों के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

जिला पंचायत सीईओ ने ली डीएलसीसी की बैठक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की तिमाही बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की प्रगति, चुनौतियों और लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की शुरूआत में एलडीएम श्री अंकित शर्मा के द्वारा बैंकों की प्रगति प्रस्तुत की गई, जिसमें सीडी रेसियो (ऋण जमा अनुपात) में वृद्धि एवं जिले के ऋण पोर्टफोलियो में 13.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने बैंकों को लंबित प्रस्तावों का शीघ्र निस्तारण कर 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात विभिन्न विभागों एनआरएलएम, एनयूएलएम, पशुपालन विभाग द्वारा भेजे गए ऋण प्रस्तावों की समीक्षा की गई। साथ ही व्यक्तिगत उद्यमी ऋण हेतु बैंको को भेजे गए प्रस्तावों की जानकारी प्रस्तुत की गई। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने कहा कि शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना बैंकों और विभागों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित ऋण प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी पहल के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रस्तावों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश बैंकों को दिए। साथ ही एनआरएलएम, एनयूएलएम और पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा भेजे गए ऋण प्रस्तावों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार और कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने प्रत्येक बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए बैंकों से ग्राहकों को अधिक ऋण उपलब्ध कराकर जिले के सीडी रेसियो (ऋण जमा अनुपात) में सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर ऋण वितरण में वृद्धि तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही।

बैठक में जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड श्री अनुपम तिवारी द्वारा जिले में कार्यरत एफपीओ की जानकारी देते हुए नाबार्ड की एफपीओ वित्तपोषण योजनाओं के बारे में बताया गया। श्री सत्येन्द्र राठौर ने सी केवाईसी आईडी के उपयोग की जानकारी दी गई तथा बैंकों को अपने सेवा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

बैठक में एलडीएम श्री अंकित शर्मा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक श्री सत्येन्द्र राठौर और जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड श्री अनुपम तिवारी सहित जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रेलवे में भृत्य पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। रेलवे में भृत्य पद पर नौकरी लगवाने के नाम एक युवक से ठगी मामले में लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। जयनगर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत आमगांव निवासी प्रार्थी बालरूप सिंह ने 4 मई 2025 को थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि माह सितम्बर 2023 में इसके परिचित अज्जू सिंह पिता बुढ़न सिंह निवासी ठाकुरपुर थाना गांधीनगर द्वारा रेलवे विभाग में भृत्य की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 38 हजार 6 सौ रुपए लिया था। नौकरी नहीं लगने से 70 हजार रूपये वापस किया शेष रकम को वापस नहीं किया है। अज्जू सिंह द्वारा नौकरी लगाने के नाम रकम लेकर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले में पुलिस ने पूर्व में 6 मई 2025 को आरोपी अज्जू सिंह को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में अपने सहयोगी सुदामा दास के साथ मिलकर एक राय होकर रेलवे

विभाग में भृत्य का नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी और उसके भाई से विभिन्न माध्यमों से कुल 238600 रुपए लिए जाने की बात स्वीकारी थी।मामले में आरोपी सुदामा फरार था। एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर प्रभारियों को लंबित मामलों में आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। जयनगर पुलिस फरार आरोपी की पतासाजी में लगी थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुदामा दास पिता स्व. समल दास 48 वर्ष निवासी मरौल बरडीपाटोला थाना बगीचा जिला जशपुर को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने अज्जू के साथ मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। कार्यवाही में जयनगर थाना प्रभारी रूपेश कुन्तल एक्का, एसआई सोहन सिंह, प्रधान आरक्षक रजिन्दर एक्का, आरक्षक हरिशंकर सिंह, सुरेश साहू, अम्बिका मरावी सक्रीय रहे।

शासन की योजनाओं और वित्तीय सहयोग से लखपति दीदी बनीं मनबासों

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले के विकासखण्ड वाड्रफनर के ग्राम पंचायत अमरावतीपुर की मनबासों, उन्नति महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ कर न केवल अपने जीवन बदली, बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी बन गई हैं। कभी आर्थिक तंगी से जुझने वाली मनबासों आज आत्मनिर्भर बनकर लखपति दीदी के रूप में जानी जा रही है।

मनबासों की परिवार आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। सीमित संसाधनों में परिवार का भरण-पोषण पूरा करना भी कठिन था। जिससे बेहतर भविष्य की कल्पना भी मुश्किल लगती थी। इस दौरान महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ने का फैसला मनबासों के जीवन में बदलाव लेकर आया। इससे उन्हें नियमित आय का साधन मिला।

मनबासों को समूह से सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 60 हजार और बैंक से नकद ऋण के रूप में 3 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई। समूह से मिली राशि से मनबासों ने किराना और पूजा सामग्री की दुकान स्थापित किया। जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। अपनी लगन और मेहनत से अब मनबासों लाखों रुपए आय अर्जित कर लखपति दीदी बन गई है। वे बताती हैं कि जहां उनकी परिवारिक आय पहले हजारों रूपये तक सीमित थी, समूह में अब जुड़ने के बाद सालाना 3 लाख रूपये की आय अर्जित कर रहीं हैं। जिससे बच्चों की उच्च शिक्षा और परिवार में सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हैं। मनबासों कहती है कि ग्रामीण महिलाएं केवल कृषि और मजदूरी पर निर्भर नहीं हैं। बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ और ऋण के रूप में वित्तीय सहयोग लेकर आत्मनिर्भरता की राह में अग्रसर हो रहीं है। साथ ही स्वावलंबन और सशक्तिकरण की मिसाल दे रहीं हैं।

योजना का लाभ लेकर सीमा बनी बिजली उपभोक्ता से ऊर्जादाता

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल के बोझ से मुक्त होने के साथ बिजली बेचकर ऊर्जादाता के रूप में नई पहचान भी बना रहे हैं। बलरामपुर जिले अंतर्गत ग्राम नवकी निवासी श्रीमती सीमा द्विवेदी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, जिससे उनको बिजली बिल से मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिली सब्सिडी से सोलर पैनल लगवाना काफी आसान हो गया है। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार से 30 हजार रुपये कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सब्सिडी के कारण आम नागरिक भी आसानी से सौर ऊर्जा को अपना पा रहे हैं। श्रीमती सीमा बताती हैं कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनका मासिक बिजली बिल हजारों रुपए के बीच आता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वे कहती हैं कि पहल हम बिजली के उपभोक्ता थे, लेकिन अब योजना का लाभ लेकर ऊर्जादाता बन गए हैं।

श्रीमती सीमा ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण भी तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक बिजली उत्पादन में होने वाले प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मुकाबले सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ है। वे अन्य नागरिकों को भी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी कर रहीं है। श्रीमती सीमा ने योजना के लिए केंद्र और राज्य शासन का आभार जताया।

कोयला चोरों को पुलिस के संरक्षण का आरोप, प्रबंधन को खुद उतरना पड़ा मैदान में, 6 आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की आमगांव, अमेरा एवं गायत्री खदानों में संगठित रूप से हो रही कोयला चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना बड़ी मात्रा में कोयला पार होने से प्रबंधन चिंता में है। आरोप है कि जब खदान प्रबंधन के अधिकारी चोरी की लिखित शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं तो पुलिस द्वारा कथित रूप से नामजद शिकायत करने या शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। इससे चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। लगातार हो रही वारदातों से परेशान प्रबंधन ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। दो दिन पूर्व क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह और सब एरिया मैनेजर आमगांव विजय कुमार लिखित माफीनामा लिया गया और प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा प्रवेश न करने की चेतावनी

त्रिपुरा बटालियन के जवानों के साथ तड़के खदान क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान कोयला ले जाते कुछ लोगों को पकड़कर उनसे देकर छोड़ा गया था। अचानक कार्रवाई के दौरान कई लोग मौके से फरार हो गए थे।

मंगलवार को एक बार फिर सुबह करीब साढ़े छह बजे महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, त्रिपुरा बटालियन के जवानों के साथ औचक दबिश देने पहुंचे। टीम को देखते ही कई संदिग्ध भाग निकले, जबकि जवानों ने छह लोगों को पकड़ लिया। उनके पास से दस बाइक और छह मोबाइल जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों को रामानुजनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रबंधन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। एसईसीएल के सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण ने बताया कि कोयला चोरी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संजयनगर में राशन वितरण को लेकर बवाल, 70 किलो में 400 ग्राम कटौती

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत संजयनगर में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान इन दिनों विवादों में घिर गई है। गांव की ओम शांति महिला समूह द्वारा संचालित इस राशन दुकान पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि राशन दुकान का संचालन मनमर्जी से किया जा रहा है, वितरण का कोई तय समय नहीं है और निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रति 70 किलो चावल में लगभग 400 ग्राम तक कटौती की जा रही है। जब इस संबंध में लाभार्थियों ने विरोध जताया तो कथित तौर पर समूह संचालक ने साफ शब्दों में कहा कि चावल की कमी है, इसलिए कम देना पड़ेगा। जहां शिकायत करना है, कर दीजिए। इस कथन ने ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों के अनुसार पूरी दुकान का संचालन और वितरण कार्य एक ही महिला द्वारा किया जाता है। इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई हितग्राहियों का कहना है कि तौल के

समय किसी प्रकार की निगरानी या सत्यापन की व्यवस्था नहीं रहती है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि राशन दुकान के खुलने का कोई निर्धारित समय नहीं है। लाभार्थियों का आरोप है कि जब समूह संचालक का मन होता है, तभी दुकान खोली जाती है। कई बार दूर-दराज से आए हितग्राहियों को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि सर्वर डाउन है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वर डाउन की बात बार-बार दोहराई जाती है, जिससे संदेह और गहरा हो रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञात हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि मात्रा में कटौती या अनियमित वितरण की शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो यह सीधे गरीब परिवारों के हक पर चोट मानी जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तौल की व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए और दुकान के खुलने का निश्चित समय तय किया जाए।

नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र से कई लोगों को मिला नया जीवन

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नशे की लत से ग्रस्त लोगों को नई दिशा दे रहा है, साथ ही उनके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का सशक्त माध्यम भी बन रहा है।

कई लोग गलत संगति के कारण शराब, गांजा, भांग, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा एवं तंबाकू जैसे अनेक नशीले पदार्थों की लत में फँस जाते हैं। नशे की वजह से उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक तंगी और सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ने कई परिवारों के जीवन को नई दिशा दी है। नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को पुन: मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नशा मुक्ति केंद्र में निर्धारित दिनचर्या अनुसार गतिविधियां कराई जाती है। केंद्र में समय-समय पर विशेष स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचाराधीन लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें बेहतर जीवन जीने हेतु

परामर्श भी दिया जाता है। चिकित्सकों द्वारा समझाईश दी जाती है कि नशा से पाचन तंत्र, हृदय और लिवर पर सर्वाधिक असर पड़ता है। इसलिए नशीले पदार्थों से दुरी बनानी चाहिए। साथ ही प्रेरक गतिविधियाँ एवं अनुशासित जीवनशैली के लिए प्रेरित किया जाता है। ताकि वे नशे की लत से बाहर आ सके।

केन्द्र में रहने वाले कई मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मरीजों ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र का माहौल और यहाँ दी जा रही चिकित्सा सेवा उन्हें घर जैसा अहसास कराती है। यहाँ उपचार के साथ-साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से आत्मविश्वास मिल रहा है। समय-समय पर काउंसलिंग भी किया जाता है। साथ ही दैनिक दिनचर्या अनुसार विभिन्न गतिविधियां भी कराई जाती है।

नशा मुक्ति केंद्र के संचालक ने बताया अब तक लगभग 478 से अधिक नशा पीड़ित ठीक होकर बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि सही मार्गदर्शन, इच्छाशक्ति और परिवार के सहयोग से नशे की लत से मुक्ति संभव है।

उल्लेखनीय है कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए शासन-प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति जैसे कार्यक्रम को प्राथमिकता से लेते हुए प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग रह रही महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका

दुर्ग, छ.ग. फ्रंटलाइन। भिलाई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही गर्लफ्रेंड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत में हो गई। वह लिव-इन पार्टनर साथ पी रहे थी। इस दौरान गर्लफ्रेंड के नाक से खून निकलने लगा। हालत बिगड़ने पर बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गर्लफ्रेंड का नाम राजिंदर कौर (35) है। वह लिव-इन पार्टनर राजा नाथ (नाग) के सेक्टर-2, स्ट्रीट-12 में तीन साल से रह रही थी। राजिंदर शादीशुदी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन वह पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी।जांच में सामने आया है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अक्सर विवाद होता था। ऐसे में राजिंदर के परिजनों में हत्या की आशंका जताते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस पूरे मामले में भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। दरअसल, राजिंदर कौर का राजा नाथ के साथ प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहते थे। 5 फरवरी की रात दोनों शराब पी रहे थे। इस दौरान अचानक राजिंदर के नाक से ब्लड आने लगा। किसी तरह उन्होंने ब्लड रोकने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और राजिंदर की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद राजा नाथ की मां ने राजिंदर को जिला अस्पताल दुर्ग लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 6 फरवरी को मौत की पुष्टि हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बाद में शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। राजिंदर कौर की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी देर से दी गई। राजिंदर की भांजी कृतिका ने बताया कि राजा नाथ की मां ने उन्हें 6 फरवरी दोपहर करीब 2 बजे घटना की जानकारी दी। परिजनों का कहना है कि राजिंदर कौर और राजा नाथ के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राजिंदर घर आती थी, उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते थे। ऐसे में परिवार को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है।

टकराने पर ट्रेलरों वाहनों में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला

जांजगीर, छ.ग. फ्रंटलाइन। अकलतरा-बलौदा मेन रोड पर कोटगढ़ के पास सुबह करीब 5 बजे तीन ट्रेलरों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर में देखते ही देखते आग लग गई और चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. हादसे में एक अन्य चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर की आशंका जताई जा रही है. हादसे के चलते कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा।

एशिया के नियाग्रा फॉल में बिखरेगी सांस्कृतिक छटा, चित्रकोट महोत्सव 18 से

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। विश्व प्रसिद्ध और एशिया के नियाग्रा के नाम से विख्यात चित्रकोट जलप्रपात के तट पर 18 फरवरी से दो दिवसीय चित्रकोट महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से आयोजित इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन 18 फरवरी को संध्या 4 बजे चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में होगा। यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर चमकाने का सुनहरा अवसर साबित होगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री केदार कश्यप रहेंगे, जबकि अध्यक्षता बस्तर के सांसद महेश कश्यप करेंगे। अति विशिष्ट अतिथियों में जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव और चित्रकोट विधायक विनायक गोयल शामिल होंगे। दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पांडेय, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, जिला पंचायत बस्तर के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, केंद्रीय मर्यादित बैंक बस्तर के अध्यक्ष दिनेश कश्यप तथा चित्रकोट के सरपंच भंवर मौर्य भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे।

संस्कृति, कला और खेल का अनोखा संगम

महोत्सव बस्तर की लोक संस्कृति को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेगा। स्थानीय लोक कलाकारों की मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसी रोमांचक खेल प्रतियोगिताएं इसकी मुख्य आकर्षण होंगी। चित्रकोट जलप्रपात के मनमोहक परिवेश में आयोजित यह उत्सव पर्यटकों को बस्तर की जनजातीय परंपराओं, नृत्य-गीत और हस्तशिल्प से रूबरू कराएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का पर्यटन मानचित्र और मजबूत बनेगा। आयोजन समिति ने सभी नागरिकों को इस सांस्कृतिक उत्सव में सादर आमंत्रित किया है।

लोक अदालत में होगा लंबित ई-चालानों का निराकरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। वाहन स्वामियों के लिए लंबित ई-चालान से सम्बंधित मामले पर एक राहत भरी खबर है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके और अब तक भुगतान न किए गए ई-चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने निर्देश दिया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित वाहन को जब्त

कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में प्रकरण रखने के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व जारी हुए और अब तक लंबित ई-चालान प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के निकटतम यातायात थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

आयकर विभाग ने सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स फैक्ट्री पर मारा छापा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने तड़के छापामार कार्रवाई की। यह कंपनी कोका कोला ब्रांड के पेय पदार्थों का निर्माण करती है। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और संभावित टैक्स चोरी से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। प्रदीप अग्रवाल इसके मालिक बताए जा रहे हैं, जबकि बिलासपुर इकाई का संचालन नवनीत अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम ने फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है

और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ जारी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि कंपनी से जुड़े देशभर के अन्य ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई की जा रही है। रायपुर डिपो के अलावा उदयपुर बेवरेज (जबलपुर) और सुपीरियर ड्रिंक्स (नागपुर) में भी आयकर टीम की जांच चल रही है। फैक्ट्री के बाहर फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी अंदर-बाहर आने की अनुमति सीमित कर दी गई है। आयकर अधिकारी आय, निवेश और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

सरगुजा का पुरातत्वीय एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर कार्यशाला का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर द्वारा आज जिला पुरातत्व संग्रहालय सरगवां अंबिकापुर में 05 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से सरगुजा अंचल के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अपने आंचलिक इतिहास और संस्कृति की सम्यक जानकारी और पुरास्थलों सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के संबंध जानकारी दी जा

रही है। संचालक विवेक आचार्य और डॉ. प्रताप चंद पारख के नेतृत्व में तैयार इस 05 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 14 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और अंतिम दिन पुरास्थल का परिभ्रमण कर प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों का अध्ययन करेंगे। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत शामिल हुईं। उन्होंने प्रतिभागियों को कार्यशाला में सरगुजा अंचल के पुरातत्व और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने और सीखने के लिए शुभकामनाएं दीं। सत्र की अध्यक्षता कर साहित्यकार आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर ने आयोजन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अपनी शोध यात्रा सरगुजा एक खोज के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की और सरगुजा स्थान नाम के बारे में विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। शुभारंभ सत्र को वरिष्ठ अध्येता श्रीश मिश्रा, पीजी कॉलेज में इतिहास की विभागाध्यक्ष डॉ. ममता गर्ग ने भी संबोधित किया और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आज के तकनीकी सत्रों में श्री श्रीश मिश्र ने रामगढ़ के गुफालेखों के ऐतिहासिक महत्व पर, बोधगया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. सचिन मंदिलवार ने सरगुजा के रियासत कालीन इतिहास और पुरातत्व पर और अजय कुमार चतुर्वेदी ने सरगुजा अंचल की लोक संस्कृति और उनके संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

सरकारी स्कूल में बाइबल बांटने वाला व्याख्याता निलंबित

जशपुर। बच्चों को सरकारी स्कूल में बाइबल बांटने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। बाइबल बांटने के अलावा व्याख्याता समय पर स्कूल में उपस्थित नहीं होता था और बिना पूर्व सूचना या अवकाश आवेदन दिए स्कूल से भी अनुपस्थित रहता था। कलेक्टर रोहित व्यास के जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने निलंबन की कार्रवाई की है। दीपक तिग्गा, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई, विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर द्वारा बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित रहना, विद्यालयीन समय में उपस्थित नहीं होना।

सरगुजा संभाग में GYOT कर्मयोगी प्रशिक्षण सम्पन्न, प्रशासनिक दक्षता सुदृढ़ करने बड़ा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन, क्षमता निर्माण एवं परिणामोन्मुख प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए ऋडळ कर्मयोगी संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आज कलेक्टर कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम सरगुजा सम्भागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य स्तर से अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं नोडल अधिकारी (ऋडळ

कर्मयोगी) सुश्री अंजू सिंह द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने ऋडळ प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग, भूमिका आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की गई, जिसके अनुरूप प्रशिक्षण को परिणामोन्मुख स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। मुख्य सचिव विकासशील के नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक क्षमता निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस एवं नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऋडळ कर्मयोगी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षण में अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित शिक्षण प्रणाली, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा गुणवत्ता में वृद्धि के विभिन्न आयामों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा संबंधित कार्यालयों के नामित नोडल अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। संभाग आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने अपने संदेश में कहा कि ऋडळ कर्मयोगी केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में परिवर्तन का माध्यम है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित होंगी। उल्लेखनीय है कि ऋडळ कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सतत क्षमता निर्माण कर राज्य में सुशासन की अवधारणा को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। यह पहल प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

अवैध पिस्टल के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। अवैध पिस्टल और मैग्जीन लेकर गुढ़ियारी क्षेत्र में घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुढ़ियारी पुलिस थाना की टीम को सूचना मिली थी कि उरएइ मैदान के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम सिद्धार्थ शर्मा (29) निवासी तिरंगा चौक, डीडी नगर बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल और एक खाली मैग्जीन बरामद हुई। वैध दस्तावेज मांगने पर वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 50/26 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। जब्त हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी से पिस्टल के स्रोत के संबंध में पूछताछ कर रही है।

जयपुर से शुरू होगी एआई किसान क्रांति: शिवराज सिंह चौहान लांच करेंगे भारत - विस्तार

मौसम, मंडी भाव, योजनाएं एक कॉल पर: भारत-विस्तार से किसानों को 24,7 स्मार्ट मदद - शिवराज सिंह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी को राजस्थान प्रवास पर रहेंगे, इस दौरान वे जयपुर में, देशभर के किसानों के लिए नया डिजिटल साथी भारत-विस्तारह्व लांच करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि और किसान भाइयों-बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को फोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर ऐप के जरिए मौसम, मंडीभाव, कीट-रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देगा। फेज-1 में यह सुविधा हिंदी व अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। लांच कार्यक्रम में राज्यों के कृषि मंत्री व आईसीएआर, केवीके, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य कृषि

संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देशभर के लाखों किसान वर्चुअली जुड़ेंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

जयपुर में 17 फरवरी को सुबह 10 बजे होने वाले लांच समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में किसान भाई-बहनों के अलावा मुख्य रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान के मुख्य सचिव और कृषि विभाग के आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैप, एआई हैकथॉनह्व व एग्रीकोष

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैपह्व भी लांच किया जाएगा, वहीं एआई हैकथॉनह्व एवं एग्रीकोषह्व की घोषणा भी उनके द्वारा होगी।

भारत-विस्तार: डिजिटल क्रांति

भारत-विस्तार भारत सरकार का किसान-केंद्रित, एआई-संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अलग-अलग सरकारी और वैज्ञानिक स्त्रोतों को जोड़कर किसानों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसान मौसम, मंडीभाव, कीट और बीमारी, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन और कम से कम 10 प्रमुख केंद्र सरकार योजनाओं से जुड़ी जानकारी और स्थिति देख सकेंगे।

वॉयस-फर्स्ट एआई: साधारण फोन से भी सुविधा

भारत-विस्तार को वॉयस-फर्स्ट एआई के रूप में तैयार किया गया है, ताकि साधारण फीचर फोन वाला किसान भी सिर्फ कॉल करके इसका लाभ ले सके। इसके लिए टेलीफोनी हेल्पलाइन 155261 को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, साथ ही वॉयस इनपुट-आउटपुट, वेबसाइट और मोबाइल साइट चैटबॉट जैसी सुविधाएं भी तैयार हैं, वहीं एंड्रॉयड ऐप भी जारी किया जाएगा।

मौसम, मंडीभाव, कीट-रोग और योजनाओं का एकीकृत समाधान

फेज-1 लांच के लिए भारत-विस्तार में आईएमडी से मौसम की जानकारी, एगमार्कनेट से मंडीभाव, एनपीएसएस के जरिए कीट और बीमारी प्रबंधन, एग्री-स्टैक डेटा और 10 केंद्र सरकार योजनाओं की जानकारी को जोड़ा गया है। इसके साथ ही योजना की डिटेल, आवेदन की स्थिति, लाभ की ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज कर समाधान की स्थिति देखने की सुविधा भी इंटीग्रेट की गई है, ताकि किसान को बार-बार दफ्तर या अलग-अलग पोर्टल न घूमने पड़ें।

डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत-विस्तार

भारत-विस्तार को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए किसान-केंद्रित, एआई-संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में डिजाइन किया गया है, जो प्लग-एंड-प्लेह्व मॉडल पर काम करेगा ताकि अलग-अलग सरकारी, वैज्ञानिक और बाजार संबंधी प्रणालियों को आसानी से जोड़ा जा सके। यह प्लेटफॉर्म सत्यापित एवं सुरक्षित जानकारी पर आधारित है, मल्टीमॉडल और बहुभाषी पहुंच देता है और ऐसा ढांचा प्रदान करता है, जिसे विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अपनाकर बड़े स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

वॉयस-फर्स्ट एआई, फीचर फोन और राज्यों से जुड़ाव

भारत-विस्तार को भारत सरकार द्वारा निर्मित एआई-संचालित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें वॉयस-फर्स्ट एआई के जरिए देश के किसानों तक सेवा पहुंचाने पर विशेष जोर है, ताकि फीचर फोन उपयोगकर्ता भी टेलीफोनी के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकें। फेज-1 में महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और आगे चलकर इसे अन्य राज्यों और अधिक भारतीय भाषाओं तक विस्तार दिया जाएगा, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर का कृषि डिजिटल नेटवर्क बन जाएगा व किसानों के लिए लाभकारी होगा।

आईसीएआर, केवीके व वैज्ञानिक सलाह से जुड़ा मजबूत नेटवर्क

भारत-विस्तार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, फसल प्रबंधन और सॉइल हेल्थ कार्ड आधारित मृदा सलाह को शामिल किया गया है, जिससे किसान को वैज्ञानिक और क्षेत्र-विशेष सलाह मिल सके। इससे यह प्लेटफॉर्म सिर्फ सूचना देने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से डिजिटल कृषि सलाहकारह्व बन जाता है, जो फसल और खेत के बेहतर निर्णय में मदद करेगा। यह ऐतिहासिक लांच कार्यक्रम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, दुगार्पुरा, जयपुर में आयोजित होगा।

सम्पादकीय

मोदी को न्योता बांग्लादेश की एक सार्थक शुरुआत

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उभरता राजनीतिक परिदृश्य दक्षिण एशिया की कूटनीति के लिए अहम संकेत दे रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा जाना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश है संवाद, संतुलन और सहयोग की नई संभावनाओं का। यानी बांग्लादेश ने मोदी को न्योता देकर एक सार्थक शुरुआत की है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बनी रहेगी या कुछ नरमाहट आएगी यह तो भविष्य पर निर्भर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहमान के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय बैठक है, लेकिन भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि नई दिल्ली इस परिवर्तन को गंभीरता से ले रही है। तारिक की ताजपोशी कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। 36 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। 20 साल के निर्वासन के बाद देश लौटकर उन्होंने कम समय में जनता का विश्वास अर्जित किया और बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिलाया है। यह जनादेश केवल सरकार बदलने का संकेत नहीं, बल्कि नीति-प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव की ओर भी इशारा करता है। शपथ ग्रहण समारोह इस बार पारंपरिक राष्ट्रपति भवन के बजाय ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जा रहा है। यह स्थान परिवर्तन भी एक प्रतीक है संभवतः अधिक सार्वजनिक और खुली राजनीतिक संस्कृति का। पड़ोसी देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजना बताता है कि रहमान सरकार क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सहयोग का एक मजबूत आधार रहा है। पिछले एक दशक में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन यह भी सच है कि दोनों देशों के रिश्ते समय-समय पर राजनीतिक बदलावों के साथ नए मोड़ लेते रहे हैं। तारिक ने शपथ से पहले स्पष्ट कहा है कि भारत के साथ वार्ता में बांग्लादेश के हित सर्वोपरि रहेंगे। यह बयान किसी भी संप्रभु राष्ट्र की स्वाभाविक प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने चीन को भी विकास साझीदार बताया है। यहीं से नई सरकार की संतुलन नीति का संकेत मिलता है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता और भारत की पारंपरिक भूमिका के बीच बांग्लादेश का संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर का यह कहना कि भारत के साथ संबंधों की नई शुरुआत हो सकती है, सकारात्मक संकेत है, परंतु चुनाव जीतते ही शेख हसीना की वापसी की मांग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार कुछ मुद्दों पर आक्रामक रुख अपना सकती है। ऐसे में आने वाले समय में नई दिल्ली और ढाका के बीच संवाद की गुणवत्ता ही तय करेगी कि रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई सरकार का रुख कैसा रहेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे की कहानी सहयोग की होगी या प्रतिस्पर्धा की।

आर्थिकी
सतीश सिंह

महंगाई नए आधार वर्ष के पैमाने में

> सरकार ने महंगाई को मापने का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इस क्रम में, 12 फरवरी को पहली बार जनवरी माह की खुदरा महंगाई को नए आधार पर मापा गया। नए आधार पर जनवरी 2026 में यह बढ़कर 2.75% हो गई, जो दिसंबर में 1.33% थी, और यह पिछले 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है। नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।

आगामी 10 वर्षों के लिए सरकार ने महंगाई को मापने का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इस क्रम में, 12 फरवरी को पहली बार जनवरी माह की खुदरा महंगाई को नए आधार पर मापा गया। नए आधार पर जनवरी 2026 में यह बढ़कर 2. 75% हो गई, जो दिसंबर में 1. 33% थी, और यह पिछले 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। इस दौरान, मई 2025 में यह 2. 82% तक पहुंच गई थी।

महंगाई का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन कैसा है। जब लोगों के पास अधिक पैसे होंगे, तो वे अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी। यदि आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत, जब मांग कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है, तो महंगाई घट जाएगी। सरकार आमतौर पर हर 5 से 10 वर्षों में नया आधार वर्ष चुनती है, जो साल सूखा, बाढ़, महामारी या अत्यधिक महंगाई से मुक्त हो। पुराने सूचकांक में खाने-पीने की वस्तुओं का वेटेज लगभग 50% था, जिसे अब घटाकर 36. 8% कर दिया गया है। गौरतलब है कि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसे कीमतों के लिए मानक या आधार माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस वर्ष की वस्तुओं की औसत कीमत को 100 माना जाता है। फिर, अन्य वर्षों की कीमतों की तुलना उसी आधार वर्ष से की जाती है। इससे पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई है। उदाहरण के लिए, यदि 2022 को आधार वर्ष माना जाए और उस वर्ष एक किलो आलू की कीमत 50 रुपये थी, और 2025 में वह बढ़कर 80 रुपये हो गई, तो महंगाई दर = (80-50)/50×100 = 60% है। यह फॉर्मूला खुदरा महंगाई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में उपयोग होता है। हालांकि, यह बाजार के सभी सामानों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। महंगाई को मापने के लिए एक बकेट में वैसी वस्तुओं व सेवाओं को रखा जाता है, जो महंगाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस क्रम में हर वस्तु को उपभोक्ता के बजट में उसके महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। सीपीआई सूचकांक की मदद से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) हर महीने खुदरा महंगाई की गणना करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल आम लोग ज्यादा करते हैं, जैसे कि खाद्य, कपड़े, आवास, ईंधन, स्वास्थ्य आदि। यह सूचकांक इन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है, जो आधार वर्ष 2012 के संदर्भ में होते थे और अब ये 2024 के संदर्भ में होंगे। विकास को सुनिश्चित करने के लिए महंगाई की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है ताकि जनता की घटती क्रय शक्ति, स्थिर आय, और जीवन यापन की लागत का सही आकलन किया जा सके। इससे उपयुक्त वित्तीय योजना, निवेश की सुरक्षा, मजदूरी की उचित मांग और सरकार के लिए सही मौद्रिक नीतियों का निर्धारण आसान हो जाता है। जब महंगाई का चित्र स्पष्ट होता है, तो सरकार सही कदम लेकर इन पर नियंत्रण कर सकती है, जिससे आम जनता के नुकसान को रोका जा सकता है। महंगाई बढ़ने से पैसे का मूल्य घट जाता है, और इससे पता है कि हमें कितनी ज्यादा कमाने या बचत करने की जरूरत है।

अगर महंगाई अधिक हो, तो निवेश का रिटर्न नकारात्मक हो जाता है। वहीं, सही महंगाई दर जानकर

सोना, शेयर जैसे बेहतर निवेश के विकल्प को चुनने में आसानी होती है। महंगाई के सही आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, और जरूरी वस्तुओं पर इसके असर को समझा जा सकता है। सरकारें इन आंकड़ों की मदद से ब्याज दरें और करों में बदलाव करती हैं। आंकड़ों के गलत रहने से सरकारी नीतियां जनता के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जब महंगाई स्थिर नहीं रहती, तो जनता को सही आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पिछले एक दशक के दौरान लोगों की जीवनशैली, खर्च करने के तरीके और लोगों के दैनिक आवश्यकताओं में आमूल-चूल बदलाव आया है। इसलिए, 2012 का आधार वर्ष महंगाई की सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहा था। आंकड़े वास्तविक आयों के लिए सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले सूचकांक में 299 वस्तुएं थीं, जिन्हें नए ढांचे में बढ़ाकर 358 कर दिया गया है। नए सूचकांक की मुख्य विशेषता है कि यह उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है जिन पर आज अधिकांश लोग खर्च कर रहे हैं।

अब, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईयरफोन, फिटनेस बैंड जैसे उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जबकि पहले इनका उपयोग सीमित था। इस सूचकांक में नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। नया आधार वर्ष लाने का मकसद है सब्जियों, अनाज जैसी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव से महंगाई के आंकड़ों पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। इस बदलाव से गैर-खाद्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव को भी महंगाई मापने में शामिल किया गया है, ताकि महंगाई की वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आ सके। नए सूचकांक में ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से वस्तुओं की कीमतों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। हवाई किराए, बिजली दरें, ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं और शॉपिंग की कीमतों को भी शामिल किया जाएगा।

इसी तरह, इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव का प्रभाव भी महंगाई के आंकड़ों में दिखाई देगा। ग्रामीण इलाकों में घर के किराए को सूचकांक में शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण महंगाई की तस्वीर और भी ज्यादा साफ होगी। इनके अलावा, वे वस्तुएं, जिनका उपयोग आज नहीं किया जाता है, जैसे वीडियो और ऑडियो कैसेट आदि, महंगाई मापने वाली सूची से हटा दी गई हैं। महंगाई की वास्तविक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे गलत तरीके से पेश किया गया, तो यह न सिर्फ जनता को परेशान कर सकता है, बल्कि विकास में भी बड़ी बाधा बन सकता है।

जब महंगाई की दर बढ़ती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को कम नहीं करता, जिससे बैंकों को सस्ती पूंजी नहीं मिलती और उन्हें उच्च ऋण दर पर ऋण देना पड़ता है। इससे उधार लेने की प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, और पूंजी की कमी के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाती हैं। इसलिए, महंगाई का सही स्तर समझना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आधार वर्ष में बदलाव और बकेट में उपयोगी वस्तुओं को शामिल करने से महंगाई की सच्चाई सामने आ सकती है, और सही उपाय अपनाकर विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है। नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

दिवस विशेष

सुनील कुमार महला

क्योटो प्रोटोकॉल : जलवायु समझौतों के लिए मार्गदर्शक

पर्यावरणीय दृष्टि से 16 फरवरी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल आधिकारिक रूप से लागू हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता था। इसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक (विकसित) देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम करना था, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से प्रभावित है, जिसका प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, तेज शहरीकरण, विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, परिवहन, कृषि गतिविधियां और प्रदूषण हैं, जिनसे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। ग्रीनहाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प तथा फ्लोरीनयुक्त गैसें आदि वायुमंडल में सूर्य की ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग 57.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.3% अधिक है। इस अवधि में उत्सर्जन वृद्धि में भारत का योगदान सबसे अधिक रहा, हालांकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी वैश्विक औसत से कम है। बता दें कि भारत में लगभग 3 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, जबकि वैश्विक औसत लगभग 6.4 टन है। कुल उत्सर्जन के मामले में भारत लगभग 4 गीगाटन वार्षिक उत्सर्जन के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन ऐतिहासिक योगदान विकसित देशों से कम है। जानकारी के अनुसार 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 423–425 पीपीएम तक पहुंच गई, जो औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में लगभग 50% अधिक है और जलवायु जोखिम को बढ़ा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 'साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारी' का सिद्धांत था। इसके अनुसार ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले विकसित देशों पर अधिक दायित्व डाला गया, जबकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को शुरुआती चरण में अनिवार्य उत्सर्जन कटौती से छूट दी गई। इस समझौते के अंतर्गत उत्सर्जन व्यापार, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) और संयुक्त कार्यान्वयन जैसे नवाचारपूर्ण तंत्र बनाए गए, जिन्हें फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कहा गया और इन्हीं के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा विकसित हुई, जिससे विकसित देश अन्य देशों में हरित परियोजनाओं या स्वच्छ तकनीक में निवेश करके कार्बन क्रेडिट खरीद सकते थे। भारत ने सीडीएम के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाएं विकसित कीं, जिससे तकनीकी आधुनिकीकरण, विदेशी निवेश और 'सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन' (सीईआर) क्रेडिट के रूप में आर्थिक लाभ मिला तथा भारत वैश्विक कार्बन बाजार का महत्वपूर्ण भागीदार बना। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन इसे अपनी संसद से अनुमोदित नहीं कराया, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठे, फिर भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन की सख्त वैश्विक प्रणाली विकसित की, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। आगे चलकर वैश्विक जलवायु प्रयासों को अधिक व्यापक बनाने के लिए 2015 में पेरिस समझौता अस्तित्व में आया, जिसमें लगभग सभी देशों को जलवायु कार्रवाई के साझा लक्ष्य में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2023-2024 में वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर के आसपास है और वर्तमान नीतियों के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि लक्ष्य हासिल करना कठिन दिखाई देता है। हालांकि, अब वैश्विक जलवायु नीति का केंद्र पेरिस समझौता बन चुका है, फिर भी क्योटो प्रोटोकॉल ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी। भारत ने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किए हैं। आज जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह समझौता दुनिया को उत्सर्जन नियंत्रण की जिम्मेदारी याद दिलाता है। संक्षेप में, क्योटो प्रोटोकॉल आधुनिक वैश्विक जलवायु नीतियों का आधार माना जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जब मन अशांत हो तो इष्टदेव के मंत्रों का जप करें

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये

संकलित
दर्शन

सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

काम शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है काम करते रहना

एक प्राचीन कथा के मुताबिक, ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के मस्तक और पैरों की खोज शुरू की। ब्रह्मा को शिव का मस्तक ढूंढने का और विष्णु को शिव के पैर ढूंढने का कार्य सौंपा गया। सभी देवता इसके आरंभ और अंत के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा आरंभ की और वे आगे बढ़ते गए। कई लोक पीछे छूट गए और कई युग बीत

संकलित
प्रेरणा

गए। फिर भी ब्रह्मा शिव के मस्तक का पता नहीं लगा पाए। सृष्टि का एक अंत है। सृजन एक बिंदु पर समाप्त होता है। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा उसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने एक केतकी का पुष्प देखा जो आकाश से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से पूछा, 'तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने शिव का मस्तक देखा है? यहां से शिव का मस्तक कितनी दूर है?' केतकी पुष्प ने कहा, 'मैं शिव के मस्तक से आ रहा हूं।' तो ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि शिव का एक मस्तक था और वे पुष्प लेकर नीचे आए। विष्णु का कार्य शिव के पैरों की खोज करना था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु बहुत विनम्र हैं। पालनकर्ता को हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए। रचयिता जैसा भी हो, यदि पालनकर्ता विनम्र हो, तभी पालन कार्य संभव है। व्यवसाय आरंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सतर्क, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार डूब जाएगा। विष्णु की विनम्रता ने ही उन्हें शिव के चरणों को ढूंढने का कार्य करने योग्य बनाया। युगों तक यात्रा करने के बाद, विष्णु शिव के चरणों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए।

अंतर्मन

आज की पाती

महाशिवरात्रि : भीतर के अंधकार से संवाद

महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का वह विराट क्षण है जहां आस्था, दर्शन और आत्मबोध एक-दूसरे से संवाद करते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की यह चतुर्दशी, शिव-तत्त्व के स्मरण और साधना का पर्व है- वह शिव, जो संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन और कल्याण के अधिष्ठाता हैं। भारतीय दर्शन में शिव को आदि और अनंत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि नवसृजन के भी मूल स्रोत हैं। शिव का डमरु ब्रह्मांड की लय को उद्घोषित करता है, गंगा का अवतरण करुणा का प्रतीक है और भस्म-विभूषण यह संदेश देता है कि भौतिकता अंततः नश्वर है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना की रात्रि है।

- जगदीश पाठक, बेमेतरा

ट्रेंड

कांग्रेस की बौखलाहट

कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए आज जब हम अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, टनल्स, ऊंचे-ऊंचे ब्रिज और आधुनिक एयरफील्ड्स के साथ देश की सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं, तो वो बौखलाहट से भर गई है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिक्षा से रोजगार तक

औद्योगिक विकास के साथ-साथ कौशल विकास को केंद्र में रखा गया है, उद्योग-अकादमिक साझेदारी, अप-स्किलिंग, एआई और डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि शिक्षा से रोजगार तक का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो और स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलें।

- धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

किसानों से विश्वासघात

हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के नाम पर भारत के किसानों के साथ हो रहे विश्वासघात को देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं,. डीडीजी आयात करने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब भारतीय पशुओं को जीएम अमेरिकी मक्के से बना डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाया जाएगा?

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

सोलर से समृद्धि

दिल्ली ने सोलर से समृद्धि का रास्ता प्रशस्त कर लिया है। अब किसान बिना एनओसी के कृषि भूमि पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। हमारी सरकार ने प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि किसानों की आय बढ़े।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

नाइजीरिया में हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित अर्गुगु शहर में हरियाली के बीच बहने वाली मतान फदान नदी में शनिवार को हजारों मछुआरे मछली पकड़ने के पारंपरिक पर्व में शामिल हुए। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू सहित हजारों दर्शकों ने सबसे बड़ी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। हालांकि सुरक्षा संबंधी कारणों से कुछ लोगों ने उत्सव से दूरी बनाए रखी। इस पर्व पर मछली पकड़ने के लिए लोगों ने हाथ से बुने जाल और लौकी से बने बर्तन जैसे केवल पारंपरिक समानों का इस्तेमाल किया। कुछ ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए केवल हाथों से ही मछली पकड़ी। इस साल के विजेता ने 59 किलोग्राम की क्रोकर मछली पकड़ी। प्रतियोगिता के विजेता को नकद इनाम दिया जाता है, जबकि बाकी प्रतिभागी अपनी पकड़ी मछलियां बेचते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साल के बाकी समय इस नदी में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती और इसकी देखरेख एक पदवीधारी प्रमुख करते हैं, जिन्हें 'सरकिन रुवा' यानी पानी का मुखिया कहा जाता है। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता वार्षिक अंतरराष्ट्रीय मछली पकड़ने के उत्सव का समापन था। पर्व के दौरान पारंपरिक कुश्ती, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।

ऑफ बीट

रूमाल या टिश्यू, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन बेहतर

आज, हम जानते हैं कि नाक से निकलने वाले स्राव में ठंडे प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जो कई सतहों पर स्थानांतरित हो सकते हैं - हाथ, रूमाल, टिश्यू,

दरवाज़े के हैंडल, कीबोर्ड - कभी-कभी शुरुआती जोखिम के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले सूती रूमाल में अपनी नाक साफ करना, फिर किसी अन्य वस्तु को छूना, इसका मतलब है कि ये वायरस फैल सकते हैं। यहां तक कि अगर आप अपने सूती रूमाल को तुरंत धोने के लिए रख देते हैं, तो भी आप दरवाजे की कुंडी जैसी सतहों को दूषित कर देंगे, और वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए अपने संक्रमित हाथों का उपयोग करेंगे। वायरस टिशू पर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। बशर्ते आप टिश्यू का उपयोग करने के बाद उन्हें फेंक दें, और उन्हें दूसरों के उठाने के लिए इधर-उधर नहीं छोड़ें, तभी इस्तेमाल किए गए टिश्यू से दूसरों तक रोगाणु पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। फिर सवाल यह है कि क्या रुमाल या टिश्यू खांसी और सांस के रास्ते निकलने वाले थूक को रोकने के लिए प्रभावी हैं। रूमाल जैसे बुनियादी कपड़े के आवरण, टिश्यू की तरह, थूक को पकड़ सकते हैं। लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि वे श्वसन एरोसोल को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं करते हैं।

चुनाव से पहले असम में दिखी तमाशेबाजी

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन ने अचानक दिया इस्तीफा दिल्ली तक मचा हड़कंप फिर 4 घंटे बाद पलटे और लिया वापस

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों सुर्खियों में रहे

एजेंसी ▶▶ गुवाहाटी

असम की सियासत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा एक बड़ी तमाशाबाजी सामने आई। इसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुर्खियों में ला दिया। पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पहले पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल मचा दी और फिर महज 4 घंटे के भीतर यू-टर्न लेते हुए कांग्रेस में ही बने रहने का ऐलान कर दिया।

पार्टी में अनदेखी और उचित सम्मान न मिलने की बात कही

सवाल खड़ा हुआ और राजनीति के जानकारार करहने लगे अचानक ऐसा क्या हुआ, जिसने एक बड़े फैसले को पल भर में बदल दिया। सोमवार सुबह भूपेनने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने पार्टी में अनदेखी और उचित सम्मान न मिलने की बात कही। इस्तीफे की खबर बाहर आते ही असम कांग्रेस में खलबली मच गई। गुवाहाटी स्थित उनके घर पर नेताओं का तांता लग गया।

भूपेन ने नेतृत्व पर साइडलाइन करने का लगाया था आरोप

इस्तीफा वापस लेते वक्त भूपेनने कहा कि मैंने अभी इस बारे में अपने परिवार से बात नहीं की है। इसलिए मुझे फैसला लेने के लिए और समय चाहिए। 32 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करने वाले भूपेन ने साइडलाइन करने का आरोप लगाया था। भूपेन ने 2021 से 2025 के बीच असम कांग्रेस संगठन की कमान संभाली थी। पिछले वर्ष पार्टी नेतृत्व ने बदलाव करते हुए उनकी जगह गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। सियासी अनुभव की बात करें तो बोरा असम विधानसभा में दो बार विधायक भी रह चुके हैं।

भूपेन बोरा

हाईकमान की दखल बनी निर्णायक

इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस हाईकमान की भूमिका निर्णायक रही। पार्टी के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद भूपेन बोरा से बात की। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी पुष्टि की कि भूपेन बोरा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। हाईकमान ने उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला संभल गया।

फैसले लेने को मजबूर हो गया

इस्तीफा देते वक्त भूपेन ने कहा था कि वह 32 साल से कांग्रेस के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में बने हालात ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया। उन्होंने यह भी साफ किया था कि वह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे, इस पर फैसला नहीं किया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त आया, जब असम में मार्च-अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान होना बाकी है।

सीएम सरमा बोले- भाजपा से संपर्क नहीं किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भूपेन का यह कदम पहले से अनुमानित था, क्योंकि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर गौरव को जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं, जिनके पिता प्रभावशाली हों या जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हों। उन्होंने यह भी दावा किया कि बोरा असम कांग्रेस के आखिरी बड़े हिंदू चेहरा थे, जिन्हें लगातार साइडलाइन किया जा रहा था। हालांकि सरमा ने यह भी कहा कि बोरा ने भाजपा जॉइन करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/अ-20(1)/2025-25,
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिवेश मणि पाठक पिता स्व० सुरेश मणि पाठक, जाति ब्राम्हण, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला सत्तीपारा, नगर अम्बिकापुर, शीट नंबर 02 स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 672/7 रकबा 0.05 एकड भूमि की लीज समाप्ति तिथि 31.03.2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवकता के माध्यम से दिनांक 08/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः-17/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम कुसमुसी प.ह.न.
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मंगलू पित्ता बुद्धु जाति कंवर निवासी ग्राम कुसमुसी. प.ह.न. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के दादी टावा मृत्यु दिनांक 15-10-2010 को ग्राम कुसमुसी में हुई है. अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने दादी टावा का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमूसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 27/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०//अ-20(3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती अंगूरी देवी जौजे रामनिवास अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-08 मोहल्ला बरेजपारा,, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2602/46 रकबा 0.02.3/4 एकड़ एवं शीट नंबर 08 मोहल्ला- न्यू महामाया रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लॉट नंबर 2559/17 रकबा 0.07.1/4 एकड़ भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अमीना खातून पत्नी सलीम खान, निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा ग्राम रनपुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 1/34 रकबा 0.016 हे० भूमि पर से विक्रेता मो. तेसामुद्दीन आ० मो. नईमुद्दीन, निवासी ग्राम महादेव पारा श्रीगढ़, तहसील अम्बिकापुर से दिनांक 03.07.2020 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से कय किया गया है, आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण बावत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09/03/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।आज दिनांक 13/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिति तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०//अ-20(3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक विपिन मित्तल आ० रौशन लाल मित्तल, जाति अग्रवाल, निवासी पैलेस रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-08 मोहल्ला खरसिया रोड, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2824/4 रकबा 0.02, 1/4 एकड भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदगुदा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

मंडल आयुक्त द्वारा तहसील नगर पंचायत एवं कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों का किया निरीक्षण

सोनभद्र। राजेश प्रकाश, मंडल आयुक्त विंध्याचल मंडल मीरजापुर ने आज जनपद भ्रमण के दौरान तहसील राबर्ट्सगंज, कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों एवं नगर पंचायत चुर्क/गुरमा का निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, साफ-सफाई, वाद-निस्तारण एवं नागरिक सुविधाओं की स्थिति का गहन अवलोकन किया। तहसील रावर्ट्सगंज के निरीक्षण के समय मंडल आयुक्त ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसील परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, अनावश्यक रूप से रखी गई सामग्रियों की नीलामी कर परिसर को सुव्यवस्थित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मुकदमों एवं वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अभिलेखागार एवं रिकॉर्ड व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। इसके पश्चात मंडल आयुक्त ने नगर पंचायत चुर्क/गुरमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देश दिए कि नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति निर्बाध एवं सुचारू रूप से की जाए। साथ ही नियमित साफ-सफाई, नालियों की सफाई तथा कूड़ा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने एवं कर संग्रहण को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। मंडल आयुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान शिकायत कक्ष, जिला आपदा प्रबंधन कक्ष, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कक्ष, न्यायालय सहायक कक्ष, अभिलेखागार कक्ष एवं रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने खतौनी संख्या 1359, 60, 61 एवं 62 का अवलोकन कर अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की उपस्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

न्यायलय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिबालकी भगत आ०. सोमर साय भगत निवासी लब्जी थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने माता (स्व मानकुवेर आ०/पति ललन की दिनांक 12/12/2009 को स्थान निवास ...में हुई है आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यूजीलैंड के मंत्री रेटी बोले

एफटीए से दोनों देशों के रिश्तों को नई रफ्तार, एआई में सहयोग करेंगे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसी बीच न्यूजीलैंड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शेन रेटी ने इस व्यापार समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार, तकनीक और सहयोग के नए अवसर खोलेगा। यह एफटीए न सिर्फ आर्थिक संबंध मजबूत करेगा, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड की रणनीतिक साझेदारी को भी नई ऊंचाई देगा। रेटी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले से ही अच्छे और गहरे संबंध हैं और यह एफटीए उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का अगला कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को व्यापार, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिलेगा। रेटी ने भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में, की भी सराहना की।

भारत ने अपने सीमाई इलाकों पर सुरक्षा को मजबूत किया

ईएलएफ के परीक्षण से सड़क पर उतर रहे सैन्य विमान

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार (15 फरवरी) को मोरान बायपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) के सफल परीक्षण के साथ भारत ने अपने सीमाई इलाकों पर बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। दरअसल, इस हाईवे पर भारतीय वायुसेना का सी-130जे सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट उतरा है, जो कि अपने वर्ग में सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी सवार थे। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो भारत की ओर से जिस तरह से अब पूर्वोत्तर में भी एक हाईवे को विमानों के रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया है, यह चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है।

असम में सी-130जे सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट उतरा

वैकल्पिक रनवे तैयार किए

भारत में हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की तकनीक को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) कहा जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के भीतर ही निर्मित एक वैकल्पिक रनवे होता है, जिसे विशेष रूप से सैन्य और आपातकालीन जरूरतों के लिए डिजाइन किया जाता है। इन हाईवे स्ट्रिप्सको भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के समन्वय से बनाया जाता है। इन्हें विशेष पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (पीक्यूसी) से तैयार किया जाता है, ताकि ये आधुनिक विमानों के उतरते समय पैदा होने वाली अत्यधिक गर्मी और उनके भारी वजन को सहने लायक क्षमता के बन सकें।

देश में 28 स्थान चिन्हित

केंद्र सरकार और वायुसेना ने देश में कुल 28 ईएलएफ साइट्स की पहचान की, जो आपात स्थितियो में लड़ाकू विमानों के लिए अहम साबित हो सकती हैं। भारत में मौजूदा समय में लगभग 15 ऐसे ईएलएफ चालू हो चुके हैं, जो राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे और पूर्वोत्तर के रणनीतिक क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इनमें यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, और राजस्थान में एनएच-925ए जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं।

वायु शक्ति को सुरक्षित रखने में सक्षम

युद्ध की स्थिति में अगर मुख्य हवाई पट्टियां ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो ये ईएलएफ वायुसेना को एक सुरक्षित बैकअप के तौर पर विकल्प प्रदान करते हैं। इन पर विमानों में जल्दी से रिफ्यूलिंग (ईंधन आपूर्ति) और रिआर्म (हथियारों को लोड) किया जा सकता है, जो युद्ध क्षेत्र में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए अहम है। ये 40 टन तक के लड़ाकू विमानों- जैसे राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज और 74 टन तक के भारी विमान भी उतर सकते हैं।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका सुमित्रा देवी पत्नी नन्द कुमार सोनी, जाति सोनार, निवासी विश्रामपुर, तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर -03 मोहल्ला केदारपुर गुदरी रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित प्लाट नम्बर 1216/3, 1217/3, 1213, 1224/4. रकबा 0.02,1/4, 0.03,1/4, 0.02, 0.02,1/2 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भू-तल पर रकबा 167.81 वर्गमीटर, प्रथम तल पर रकबा 170. 15 वर्गमीटर परं व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित ब्लूप्रिंट नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई औपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27/02/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः-10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)
रा.प्र.क्र./202601030100002/अ-19(3)/2025-26
ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07. तहसील जशपुर
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व संबंधित ग्रामीण जनता ग्राम जशपुर, प.ह.नं. 07. तहसील जशपुर यो समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष रौनियार समाज जशपुर के द्वारा रौनियार भवन के सामने सड़क सकरा तथा बहुत व्यस्त होने के कारण भवन के सामने गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं होने से पार्किंग हेतु नजूल भूमि खसरा नं. 375 से 15 डिसमिल भूमि की मांग किये जाने पर माननीय विधायक जशपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 12/12/2025 के द्वारा पार्किंग हेतु नजूल भूमि खसरा नं. 375 से 15 डिसमिल भूमि को आबंटन किये जाने हेतु भूमि की मांग किये जाने पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर से नियमानुसार कार्यवाही हेतु टुकडा नक्शा पेश करने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 26/02/2026 को इस न्यायालय में होना नियत किया गया है। अतः उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे अपना लिखित आपत्ति स्वतः अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी

तहसीलदार
जशपुर जिला जशपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार

रा०प्र०क्र० /अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद कुमार अग्रवाल पिता कलीराम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी खरसिया रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की ममि स्थित ग्राम कांतिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 11/4, 47/3,47/4, रकबा 0.045, 0.122, 0.555 हे० भूमि को कृषि भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 25/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः 202602020700167/
विषयः- अ-6
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः-2025-2026
लक्ष्मीपुर प.ह.न. 00023 [387/8(0.02000)
पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार फुलो बाई.
अनावेदक पक्षकार-हीरालाल,
ईश्तहार

आवेदक फुलो बाई पत्नी हिरातालल निवासी दरीपारा कबीर वार्ड नंबर 44, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 387/8 रकबा 0.020 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृत भूमिस्वामी हिरालाल का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09.03.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अधवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 12/02/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील- अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
इश्तहार

रा०प्र०क्र०.../अ-2/2025-26

एक्द् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कांति खुंटे पत्नी निर्मल खुंटे जाति सतनामी निवासी कोरबा तहसील कोरबा जिला कोरबा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 198/29 रकबा 0.021 हे मूनि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूनि उपयोगिता प्रमाण पत्र, सेटलमेन्ट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उका संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई विधि 18/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.15
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामसाय पिता केवला जाति पनिका निवासी ग्राम रगदा .प.ह.न.15.रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक स्वयं रामदास का जन्म दिनांक 08/10/1998 को ग्राम रमदा में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपना स्वयं रामदास जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत रगदा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)
रा०प्र०क०.ब-121/2025-26
ग्राम परसागुडी
तहसील राजपुर
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम परसागुडी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मोहन राम आ० स्व. प्रभुराम जाति गोड निवासी ग्राम परसागुडी थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) -द्वारा अपने पिता स्व. प्रभुराम आ० हरबंश की मृत्यु ग्राम परसागुडी में दिनांक 07/09/1994 को हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानतावश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 28/02/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आंपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर काई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिका दंडाधिकारी
राजपुर जिला-बलरामपुर

न्यायालयं नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम- कुसमुसी प.ह.न. 11
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बालेश्वर पिता सरोज कुमार जाति कवंर निवासी ग्राम कुसमुसी. प.ह.न.11 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के नानी स्व मांगो का मृत्यु दिनांक 15/10/2001 को ग्राम कुसमुसी में हुई है अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने.नानी स्व मांगो का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/02/2026 आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 21/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर

कुपोषित बच्चों और एनीमिक महिलाओ पर फोकस कर सुपोषित करें : कलेक्टर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों, बच्चों की संख्या, जर्जर भवन, निमार्णाधीन भवन, पूर्ण भवन, टीकाकरण, पोषक आहार वितरण आदि का परियोजना और सेक्टर अधिकारियों से चर्चा कर समीक्षा किया।कलेक्टर ने कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों को नहीं बैठाएं। नवीन भवन निर्माण हो चुका है तो बच्चों को वहां बैठाएं। नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजें और जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने के लिए भी पत्राचार करें ताकि सभी व्यवस्थित रहे। पालकों के साथ गृह भेंट और महिलाओं के साथ

चौपाल कर बच्चों के देखरेख, सावधानी आदि के बारे में माताओं को सिखाएं।कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कुपोषित और मध्यम बच्चे हैं उन्हें एनआरसी केंद्र के माध्यम से सुपोषित करने के लिए पालक को प्रोत्साहित करने सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को निर्देशित करें ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे। इसी प्रकार बच्चों को जन्मजात या अन्य गंभीर बीमारी ग्रस्त है तो उन्हें चिरायु टीम को जांच करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने अधिकारियों और सुपरवाइजरों को महतारी वंदन योजना के नये पंजीयन नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अपने क्षेत्र के महिलाओं को दें। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी और स्टॉफ को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपके आंगनबाड़ी का निर्माण कहाँ हो रहा है, उनके निर्माण का अच्छी गुणवत्ता से हो रहा या नहीं, यह ध्यान दें और अच्छे क्वालिटी से निर्माण नहीं हो रहा तो उसकी जानकारी उच्च अधिकारियो को दें।सभी नागरिकों के बीमारी और इलाज का रिकार्ड के लिए आभा आईडी बनाने और बच्चों के पढ़ाई का रिकार्ड रखने के लिए अपार आईडी बनाये। कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती और शिशुवती माता सहित 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण और घर पहुंच राशन शत प्रतिशत वितरित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी समय पर खुले और सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को निर्देश दिए।कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत गर्भवती माताओं को लाभान्वित करें और कोई भी गर्भवती माता नहीं छूटनी चाहिए। शत प्रतिशत पोषण आहार का वितरण और पोषण ट्रैकर में इसे दर्ज होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा गर्भवती, शिशुवती और बच्चों के गृह भेंट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पोषण परामर्श सुनिश्चित करना है, उन्हें जानकारी देना है कि कौन कौन से सब्जी भाजी, फल मूल में कौन से विटामिन होता है, जिसके सेवन से शरीर मजबूत होता है। कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण होना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गिनती, अक्षर ज्ञान, नाम, पता, बोलने में झिझक को दूर करने के लिए स्कूल जाने के पहले बुनियादी शिक्षा देना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह,जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी उत्तम प्रसाद सहित सारंगढ़, बरमकेला, भटगांव, बिलाईगढ़ सरसीवा, लेंधरा, कोसीर, सरिया के परियोजना अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, सुपरवाइजर आदि उपस्थित थे।

ऑल द बेस्ट, प्यारे बच्चों : विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, प्यारे बच्चों ह्व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें आत्मविश्वास और हौसले के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों के नाम अपने आत्मीय संदेश में कहा कि परीक्षाओं का समय जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें उत्साह के साथ थोड़ा तनाव भी स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि परीक्षाओं का समय आ गया है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों आपके मन में उत्साह भी है और थोड़ा सा तनाव भी। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का समय कभी-कभी मन में घबराहट भी लेकर आता है। यह स्वाभाविक है। यदि आपको डर लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझ लीजिए डर कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। लेकिन इस डर को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। आपने पूरे वर्ष मेहनत की है। हर दिन का प्रयास, हर अभ्यास, हर दोहराव सब आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी नियमित पढ़ाई करें, कठिन विषयों को दोहराएँ, समय का संतुलन बनाए रखें। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थी इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवार तथा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

उज्ज्वला गैस, पिंक ई-रिक्शा और गार्बेज रिक्शा वितरण से आत्मनिर्भरता को मिला नया संबल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोरिया प्रवास के दौरान कोरिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में 105 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से अब इन परिवारों को धुएं से मुक्ति मिलने के साथ

सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल ईंधन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर स्व-रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 6 आजीविका दीदियों को पिंक ई-रिक्शा (ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस) प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी।

उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा - उच्च शिक्षा मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के भविष्य पर केंद्रित फ्लैगशिप कार्यक्रम ह्यशिक्षा संवाद 2026 का आज रायपुर के कोर्टयार्ड मैरियट में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने किया। इस आयोजन का संचालन उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया, जिसमें एलिट्स टेक्नोमीडिया सहयोगी संस्था के

रूप में जुड़ा रहा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार का सेतु थीम पर आधारित उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के समायोजन और क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। मंत्री ने संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप ढालने पर बल दिया। साथ ही विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के बीच संरचित समन्वय की आवश्यकता बताई, ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक दक्षता और रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो सके। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और नीतिगत सुधारों को भी गुणवत्ता सुधार का अहम माध्यम बताया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने शासन के शिक्षा सुधारों, संस्थागत सशक्तीकरण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नीति के समुचित कार्यान्वयन, डिजिटल एकीकरण और परिणाम आधारित दृष्टिकोण से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

नक्सल छाया से पर्यटन हब तक की शानदार यात्रा

विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों से खुल रहे विकास के नए द्वार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित राज्य की छवि से पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब तेजी से देश के उभरते पर्यटन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन विरासत और जीवंत आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश अब नई नीतियों और आधारभूत ढांचे के विकास के कारण राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पर्यटन अधोसंरचना को शीर्ष स्थान दिया गया है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर निवेशकों को सब्सिडी, टैक्स छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। राज्य में इको-एथनिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर संभाग की पहचान उसकी जीवंत परंपराओं से है। गोंड, मुरिया, हल्बा और बैगा जनजातियों की जीवनशैली, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और लोकनृत्य पर्यटकों

को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। पंथी, राउत नाचा, सुवा और कर्मा जैसे लोकनृत्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं। प्रदेश में स्थित प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तेजी से पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विविधताओं से देश-विदेश के सैलानियों को लुभा रहा है। चित्रकोट जलप्रपात, जिसे एशिया का नियाग्रा कहा जाता है, एडवेंचर प्रेमियों का पसंदीदा स्पॉट है। जशपुर का मधेश्वर पर्वत आकर्षित करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। रहस्यमयी कुटुमसर गुफाएं एडवेंचर थ्रिल प्रदान करती हैं। रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला राम वनवास स्थल के रूप में धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। ये सभी स्थल राज्य सरकार की विकास योजनाओं से और समृद्ध हो रहे हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित धुड़मारास गांव ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। इन स्थलों के आसपास सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की योजनाओं से पर्यटन केवल भ्रमण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह स्थानीय रोजगार का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। होम-स्टे, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन और गाइड सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की आय में वृद्धि हो रही है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख इको-कल्चरल पर्यटन राज्यों में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ नक्सल छवि से बाहर निकलकर पर्यटन की नई पहचान गढ़ रहा है और विकास की नई उड़ान भरता दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कुम्हार के चाक पर गढ़ा दीया, पारंपरिक शिल्पकारों से किया आत्मीय संवाद

सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान प्रदर्शनी में दिखा माटी से जुड़ाव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक आत्मीय और सहज रूप उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं मिट्टी का दीया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्प के प्रति सम्मान और जुड़ाव का सशक्त संदेश दिया। अवसर था सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक का, जिसमें शामिल होने वे कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे थे। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के साथ परिसर में स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसी प्रदर्शनी में सोनहत विकासखंड निवासी शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति इलेक्ट्रिक चाक पर मिट्टी से दीया और कलश बनाने का सजीव प्रदर्शन कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री साय उनके स्टॉल पर पहुंचे और कुछ देर तक उनकी शिल्पकला का बारीकी से अवलोकन किया। कला के प्रति उत्सुकता बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने स्वयं चाक पर हाथ आजमाने की इच्छा व्यक्त की। शिल्पकार की सहमति से उन्होंने घूमते हुए चाक पर रखी गीली मिट्टी को हाथों से साधा और देखते ही देखते उसे सुंदर दीये का आकार दे दिया। मुख्यमंत्री की सहज कुशलता देखकर स्वयं शिल्पकार भी आश्चर्यचकित रह गए, वहीं उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस क्षण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति से उनके व्यवसाय, आय और परिवार की जानकारी ली तथा उन्हें शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं कारीगर हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक शिल्प, कारीगरों और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि स्थानीय कला और हुनर को नई पहचान और बाजार मिल सके। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भैयालाल राजवाड़े, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रविकुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुदूर अंचलों के श्रद्धालुओं को मिला अयोध्या धाम का सौभाग्य, मुख्यमंत्री ने कहा - यही जनसेवा की प्रेरणा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान झुमका जलाशय परिसर में ह्यश्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की पावन यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का हाल-चाल जाना और उनके आध्यात्मिक एवं भक्तिमय अनुभवों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से उन्हें निःशुल्क अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सम्मानपूर्वक यात्रा की समुचित

व्यवस्था किए जाने से यह यात्रा उनके लिए अत्यंत सहज और अविस्मरणीय बन गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने सुदूर गांवों से अयोध्या तक पहुँचना उनके लिए पहले कठिन था, किंतु सरकार की पहल ने इसे संभव कर दिया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री साय को ह्यहमारे राम तैलचित्र भेंट कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और प्रदेशवासियों को उनके दर्शन कराना शासन के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही जनसेवा की वास्तविक संतुष्टि है, और सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही है।

पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहां विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका

विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अग्निवीर भर्ती आवेदन प्रक्रिया जारी, 1 अप्रैल अंतिम तिथि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय थलसेना में अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट www.joinindian-army.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती के अंतर्गत अग्निवीर (पुरुष) जनरल, तकनीकी, लिपिक/स्टोर कीपर, ट्रेडमैन (दसवीं एवं आठवीं उत्तीर्ण) तथा अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) सहित स्थायी कैडर नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट (वेट) एवं सिपाही फार्मा के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) 1 जून से 10 जून 2026 के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं।

सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में गणित के गलत प्रश्नपत्र मिलने से परेशान रहे परीक्षार्थी

0 परीक्षार्थियों को 6 घण्टे तक केंद्र में रखा गया 0 तिलसिवां मुख्यमंत्री डीएवी का मामला 0 केंद्राध्यक्ष ने बताया सीबीएसई की त्रुटि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर/ बिश्रामपुर। मंगलवार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारम्भ हो गई है। लेकिन परीक्षा के प्रथम दिवस ही गंभीर त्रुटि सामने आने से परीक्षार्थियों और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला जिला मुख्यालय स्थित डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, तिलसिवा में बनाए गए परीक्षा केंद्र का है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा आयोजित थी। गणित में छात्रों के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक दो प्रकार के प्रश्नपत्र होते हैं। आरोप है कि केंद्र में मौजूद सभी 183 विद्यार्थियों को स्टैंडर्ड प्रश्नपत्र वितरित कर दिए गए। प्रश्नपत्र देखने के बाद विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद केंद्र प्रभारी द्वारा तत्काल सभी से प्रश्नपत्र वापस ले लिए गए। इधर मामले की जानकारी कलेक्टर एस जयवर्धन तथा सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद संभाग मुख्यालय से बेसिक प्रश्नपत्र मंगाए गए और विद्यार्थियों को वितरित कर परीक्षा शुरू कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्र-छात्राओ को करीब 6 घंटे तक परीक्षा केंद्र में ही रखा गया। जिसमे वह परीक्षार्थी भी शामिल रहे जिन्होंने निर्धारत समय मे अपने प्रश्नपत्र हल कर लिए थे।

बताया गया है कि उक्त केंद्र में डीएवी पब्लिक स्कूल बिश्रामपुर और साधु राम विद्या मंदिर सहित कुल 183 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। जिनमें से लगभग 42 छात्रों ने स्टैंडर्ड गणित का विकल्प चुना था, जबकि शेष विद्यार्थियों ने बेसिक गणित चुना था। केंद्राध्यक्ष विधु शर्मा ने इसे सीबीएसई की त्रुटि बताया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों का बंडल खोलने पर सभी प्रश्नपत्र स्टैंडर्ड के पाए गए। इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी गई और उनके मार्गदर्शन में वैकल्पिक प्रश्नपत्र की व्यवस्था कर पर्याप्त अतिरिक्त समय एवं काउंसलिंग के बाद परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा के पहले ही दिन हुई इस अव्यवस्था से विद्यार्थी एवं अभिभावक चिंतित रहे। अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वाहन में ओव्हर लोडिंग पर हुआ 20 हजार जुर्माना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अशोक लिलेण्ड वाहन में अवैध रूप से ओवरलोडिंग करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। चंदौरा पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी इसी दौरान वहां अशोक लिलेण्ड बडा दोस्त वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडडी 7239 पहुंचा जिसमें फर्नीचर लोड था। वाहन में लोड फर्नीचर का

वाहन के वास्तविक रूप से बाहर अत्यधिक उंचाई में लोड़ किया होने के कारण अनुज्ञेय सीमा से परे होने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 20 हजार रूपये का समन शुल्क लिया है। पुलिस ने वाहन मालिकों व चालकों से अपील किया है कि वाहनों में हमेशा क्षमता के अनुसार ही माल लोड करें ताकि जुर्माने और दुर्घटना से बचा जा सके।

महाशिवरात्रि पर शहर में बाजे गाजे के साथ निकली भगवान भोलेनाथ की बारात

मंगलगान के साथ विधि विधान से हुई पूजा अर्चना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा भगवान भोलेनाथ के बारात की भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाडे व आतिशबाजी के साथ धूमधाम से निकाली गई। जो भैयाथान रोड स्थित पंचमंदिर से प्रारम्भ होकर मेन रोड श्रीराम मंदिर, सुभाष चौक, अग्रसेन चौक से होकर केतका रोड स्थित शिवमंदिर पहुंची।

शिव बारात का नगरवासियो द्वारा पुष्प वर्षा एवं आरती उतार कर स्वागत किया गया। शिव बारात के समापन स्थल केतका रोड के शिवमंदिर प्रांगण मे शिवभक्तों महिलाओ एवं बच्चो के द्वारा मंगलगान कर स्वागत किया गया मंदिर में पुजारी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर जयमाला एवं आरती के पश्चात् भण्डारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने मे संघ के संरक्षक भोला प्रसाद, हरिदास, बांके बिहारी व संयोजक लालचन्द अग्रवाल, अध्यक्ष अनिल गोयल सहित पवन मित्तल, आर.एस. मिश्रा, मोतीलाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, पुखराज जैन, रमेश कुमार रोहिल्ला, एस. एन. भारती, विजय सोनी, मनोहर सोनी, डुमनचंद साहू, विश्वनाथ साहू, राजकपुर रोहिल्ला, नपा उपाध्यक्ष शैलेष अग्रवाल व पंच मंदिर समिति के संरक्षक मुकेश गर्ग, बाबूलाल अग्रवाल, रामअवतार अग्रवाल, सशिमं के प्राचार्य कौलाश यादव, अनिल गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम का सक्रिय एवं सराहनीय सहयोग रहा।

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान : जिले में अब तक 1. 80 लाख लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप देश को 2030 तक फाइलेरिया बीमारी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 25 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी नागरिकों को डी.ई.सी., एल्बेंडाजोल एवं आईवरमेक्टिन दवा का संयुक्त रूप से सेवन कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.कपिल देव पैकरा ने बताया कि जिले के तीन विकासखंड सूरजपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर में 25 फरवरी तक फाइलेरिया से बचाव के लिए सामूहिक दवा सेवा अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें तीनो विकासखंड में 4 लाख 16 हजार 889 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रथम चरण अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्कूलों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ियों आदि शैक्षणिक संस्थानों में 12 फरवरी तक दवा सेवन कराया गया। इसी तरह द्वितीय चरण में 13 से 22 फरवरी तक घर-घर जाकर तथा 23 से 25 फरवरी तक छूटे हुए लोगों को मापअप राउंड अंतर्गत दवा सेवन कराया जाएगा। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी तक की स्थिति में तीनो विकासखंड में 1.79. 536 लाख अर्थात् 43.18 प्रतिशत लोगों को फाइलेरिया की दवा का सेवन कराया गया है।

नवा रायपुर का सफर होगा आसान, अगले 6 महीने में दौड़ेंगी 40 ई-बसें

रायपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मंत्रालय के कर्मचारियों और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर से नवा रायपुर के बीच अगले छह महीनों में ई-बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हो रही है, जिससे नवा रायपुर में आवागमन सुगम होगा और वहां की बसाहट को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को भी बल मिलेगा।

सात-आठ वर्षों से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने वाला

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाले लोगों के लिए पिछले सात-आठ वर्षों से चल रहा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। प्रशासन ने रायपुर और नवा रायपुर को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड को चुना है।

कंपनी को 73.80 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टेंडर दिया गया है। अनुबंध के अनुसार, वर्कआर्डर मिलने के छह महीनों के भीतर ई-बसें सड़कों पर दिखाई देने लगेंगी। यह अनुबंध 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है, जिससे परिवहन व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी।

ई-बसों के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचे पर भी काम शुरू हो चुका है। एनआरडीए ने चीचा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक डिपो का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस डिपो में बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए विशेष वर्कशाप के साथ ही बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पाइंट भी स्थापित किए जाएंगे। बसों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, ताकि लाइव मानिटरिंग की जा सके।

नई ई-बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल होंगी, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्नत होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इनमें कई विशेष फीचर्स जोड़े गए हैं। प्रत्येक बस सीसीटीवी कैमरों और जीपीएस से लैस होगी। यात्रियों को अगले स्टॉप और रूट की जानकारी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी।

रायपुर से नवा रायपुर का अधिकतम किराया 45 रुपये रखा जा सकता है। एनआरडीए के अधिकारियों के अनुसार, डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ईंधन की लागत कम होगी और रायपुर तथा नवा रायपुर के शांत वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी घट जाएगा।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगॉव जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 216/ब–121/2025–26

ईश्तहार

आम जनता ग्राम तेलगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार आ. स्व हरकलाल जाति रजवार निवासी ग्राम तेलगांव तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा अपने चाचा जवाहिर लाल मृत्यु दिनाक 19/07/2008 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने चाचा का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 24.02.2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विधार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला सूरजपुर (छ.ग)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगॉव जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 216/ब–121/2025–26

ईश्तहार

आम जनता ग्राम तेलगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक सीताराम आ. वीरसाय जाति रजवार निवासी ग्राम तेलगांव तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा अपने दादा मोतीलाल मृत्यु दिनांक 13/05/2008 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 24.02.2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विधार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला सूरजपुर (छ.ग)

ट्रैलर में लगी आग, मौके पर पहुंचा दमकल वाहन

कोरबा, छ.ग. फ्रंटलाइन। दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपका खदान में एक अनलोड ट्रैलर वाहन में अचानक आग लग गई। घटना पश्चात मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, संबंधित ट्रैलर वाहन अनलोड अवस्था में था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और धू-धू कर जल रहे ट्रैलर में लगी आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि ट्रैलर में कोयला लोड नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

इस संबंध में रोड सेल इंचार्ज संतोष सिंह ने बताया कि ट्रैलर में कोयला नहीं था। अचानक आग लगने की सूचना मिली थी, जिसे फायर वाहन की मदद से समय रहते बुझा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।

सरपंच संघ की बैठक में पंचायतों के अधिकारों को लेकर लिए गए निर्णय

निर्माण कार्यों की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा पंचायतों को अधिकृत एजेंसी बनाने की गई मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला सरपंच संघ के कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। जिसमें जिले के सभी विकासखंडों के सरपंच संघ अध्यक्ष, पूर्व जिला सरपंच संघ अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि तथा कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ग्राम पंचायतों के अधिकार, बजट एवं प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला सरपंच संघ अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम ने किया। बैठक में सूरजपुर ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष राम विलास सिंह, ओड़गी गजमोचन सिंह, प्रतापपुर नंददेव सिंह, पूर्व जिला सरपंच संघ अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह टेकाम, कपिल देव पैकरा, नीरा भागवत पैकरा, बृजलाल लकड़ा, सतवीर सिंह कोर्चो, सुनील सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान पंचायतों के समक्ष आ रही प्रशासनिक व वित्तीय चुनौतियों पर गंभीर मंथन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों को विकास

कार्यों के लिए निर्धारित 20 लाख रुपये की सीमा पर्याप्त नहीं है, जिससे बड़े और आवश्यक निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, भवन, सामुदायिक केंद्र, पेयजल, नाली निर्माण सहित कई मूलभूत सुविधाओं के कार्य लंबित रहते हैं, क्योंकि लागत सीमा कम होने से योजनाएं बाधित हो जाती हैं। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत सीमा 20 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाए। सदस्यों का मत था कि इससे पंचायतें स्वावलंबी बनेंगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी मांग की गई कि निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को ही अधिकृत एजेंसी बनाया जाए।

बैठक में कहा गया कि ग्राम पंचायतें स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझती हैं, इसलिए उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करना ही वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पारित प्रस्ताव को शासन-प्रशासन तक विधिवत रूप से पहुंचाया जाएगा और आवश्यक होने पर उच्च स्तर पर प्रतिनिधिमंडल भेजकर चर्चा की जाएगी। अंत में अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों की रक्षा, स्वायत्तता और सशक्तिकरण के लिए जिला सरपंच संघ निरंतर संघर्ष करता रहेगा।

ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के साथ मनाया गया आवास दिवस

कोरबा, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में शनिवार को चावल उत्सव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिवस तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास दिवस का आयोजन किया गया। आवास दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना, हितग्राहियों में जागरूकता बढ़ाना तथा निर्माण के दौरान आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन प्रत्येक माह की 07 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।

आवास दिवस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों को

प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने हेतु विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के माध्यम से दी गई। ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसी क्रम में मनरेगा के कार्य स्थलों पर आयोजित रोजगार दिवस के दौरान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित पम्पलेट का वितरण कर इसके प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा रोजगार अधिकारों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

दीपका एटक के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 23 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा

कोरबा, छ.ग. फ्रंटलाइन। एसईसीएल दीपका एरिया में श्रमिक संगठन एटक को बड़ा झटका लगा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 23 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। एसईसीएल दीपका क्षेत्र में एक माह पूर्व ही एटक यूनियन का क्षेत्रीय सम्मलेन हुआ था। इसके बावजूद यूनियन में इन दिनों सब कुछ ठीक नही चल रहा है। हाल ही में कुसमुण्डा क्षेत्र में मजदूर आंदोलन पर एटक के क्षेत्रीय अध्यक्ष का समर्थन रहा है।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वैध नाम कटवाने फार्म-7 का दुरुपयोग

उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने तथ्यात्मक जानकारी दी

वैध मतदाताओं का नाम कटवाने की साजिश रचने वालों के विरूद्ध हो दंडात्मक कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की जारी प्रक्रिया में फार्म-7 का उपयोग कर हजारों मतदाताओं के नाम कटवाने के संगठित प्रयास के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार नायक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि फार्म 7 का दुरुपयोग कर वैध मतदाताओं का नाम कटवाने वाले तत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

एसआईआर की प्रक्रिया के दूसरे चरण में दावा आपत्ति के दौरान अंतिम समय में भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा पूरे जिले में फार्म-7 का दुरुपयोग करते हुए हजारों लोगों के नाम कटवाने की आपत्ति दर्ज की गई। अकेले अंबिकापुर शहर में 1143 नाम कटवाने का आवेदन यह कहते हुए दिया गया ये मतदाता मौजूद नहीं है। आरोप है जान-बूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने झूठी जानकारी का शपथ पत्र देते हुए वैध मतदाताओं का नाम कटवाने का प्रयास किया है। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव, पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, राशिद अहमद, शैलेंद्र सोनी, जमील खान, हसन खान, मेराज रंगरेज, गुरूप्रीत सिंह, जीवन यादव, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, नीतीश चौरसिया, निकी खान, सोहन जायसवाल, अख्तर चम्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभावित मतदाता मौजूद थे।

नेता प्रतिपक्ष के भाई, पार्षद और उनके परिवार का नाम भी शामिल

फार्म-7 का उपयोग जिन लोगों का नाम कटवाने के लिए किया गया है, इनमें नगर निगम अंबिकापुर के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के भाई रफी अहमद, पार्षद कलीम अंसारी के पुत्र और भतीजा, पार्षद हसन खान और उनकी पत्नी, पूर्व पार्षद नुजहत फातिमा जैसे नाम शामिल हैं। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने फार्म-7 में गलत जानकारी देते हुए पूरे जिले के अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके संगठित रूप से नाम कटवाने का आवेदन दिया था। जिन लोगों के नामों को कटवाने का आवेदन दिया गया था, उनका नाम भौतिक सत्यापन उपरांत एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया।

कानूनी कार्रवाई के लिए लेंगे विधिक अभिमत

उप जिला निर्वाचन अधिकारी से चर्चा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने मांग की है कि संबंधित मतदान केंद्र के बीएलए की मौजूदगी में नाम कटवाने के लिए भाजपाइयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। अगर भौतिक सत्यापन में पाया जाता है कि नाम काटने के लिए प्रस्तुत आवेदन गलत जानकारी पर आधारित हैं तो ऐसे आवेदन को देने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि बिना भौतिक सत्यापन के ड्राफ्ट सूची में मौजूद किसी भी मतदाता का नाम विलोपित नहीं किया जाएगा। गलत फार्म-7 प्रस्तुत कर नाम कटवाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने विधिक अभिमत प्राप्त कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

न्यायालय में परिवाद की प्रक्रिया होगी प्रारंभ

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने पार्टी के सभी बूथ लेबल एजेंट सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इन फर्जी आवेदनों के विरोध में थानों में अपराध दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जिले भर में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस असंज्ञेय अपराध का मामला पंजीबद्ध कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस के द्वारा काटे गए सान्हा के आधार पर फर्जी फार्म 7 प्रस्तुत करने वाले भाजपाइयों के विरुद्ध जल्द ही न्यायालय में परिवाद की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि भविष्य में गलत तथ्यों के आधार पर वैध मतदाताओं का नाम कटवाने वालों पर लगाम लगे।

एनएच में डेढ़ घंटे मास्क लगाकर चक्काजाम, 10 दिन में गड्ढे भरने का मिला आश्वासन

अवैध प्लाटिंग और ब्लास्टिंग की होगी जांच, धूल से मुक्ति दिलाने होगी पहल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। एनएच 343 से लगे ग्राम पंचायत रनपुर में जर्जर सड़क, नाला निर्माण, जल समस्या, अवैध प्लॉटिंग व ब्लास्टिंग संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शैलेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुंह में मास्क लगाकर चक्काजाम किया। ने दी है। करीब डेढ़ घंटे तक चले चक्काजाम के दौरान सड़क मार्ग में दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतार लग गई। इसकी सूचना मिलने पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और इनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर ज्ञापन सौंपकर चक्काजाम समाप्त किया गया।

शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आसपास के ग्राम पंचायतों में सड़क की जर्जर स्थिति से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही, सड़क निर्माण के दौरान अत्यधिक धूल उड़ रही है एवं कई स्थानों पर मिट्टी एवं धूल को सड़क के किनारे एवं मोड़ के पास डंप कर दिया गया है, जिससे धूल उड़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ निखिल कुजूर द्वारा आश्वासन दिया गया कि धूल से निजात दिलाने के दो गाड़ियों से लगातार पानी का रिसाव कराया जाएगा। 10 दिन के अंदर सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे और पूरा काम समय-सीमा में करा लिया जाएगा। पेयजल के लिए ईई पीएचई ओमकार सिंह ने बताया कि साल भर में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण होगा और बांकी डैम से पानी का सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद ग्राम असोला, रनपुर, देवगढ़, सोनपुर में अप्रैल तक कुछ बोरिंग की सुविधा प्रदाय कर दी जाएगी। वहीं नायब तहसीलदार ने अवैध प्लाटिंग और ब्लास्टिंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है। इस दौरान शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ निखिल विश्वकर्मा, सौरभ फिलिप, आशीष शील, तरण बाबरा, प्रिंस विश्वकर्मा, वैभव पांडेय, ज्ञान तिवारी, निकेश यादव, सरपंच असोला दीपक पैकरा, भानु राजवाड़े, सौरभ विश्वकर्मा, फैज, विजय शर्मा, नवीन गुप्ता, लाली, सोनमणि, रामकुंवर, विलासो, पूर्णिमा, तुलेश्वरी, संतोषी, जीधन यादव, सोनू यादव, ललन दास, मुकेश दास, मोनू यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

ट्रेन आगे बढ़ने से पटरी में गिरी महिला, इलाज के दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मथुरा से सत्संग में शामिल होकर लौटी महिला, ट्रेन के आगे बढ़ने पर प्लेटफार्म से पटरी में गिर गई। यात्रियों ने इमरजेंसी चैन को खींच दिया, जिससे ट्रेन रूक गई।

महिला को बाहर निकालकर स्वजन नजदीकी अस्पताल ले गए, यहां से रेफर करने पर अंबिकापुर लेकर आए, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक कोरिया जिला के पटना थाना अंतर्गत ग्राम खाड़ा चिटकाही की चन्द्रावती साहू पति शिवराम साहू 55 वर्ष, 12 फरवरी को सपरिवार मथुरा में आयोजित सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी। वापसी दौरान 16 फरवरी को सुबह करीब 09 बजे वे चरचा रेलवे स्टेशन पहुंचे। चन्द्रावती का हाथ पकड़कर उनका पुत्र राजकुमार ट्रेन से उतार रहा था, इसी बीच अचानक ट्रेन बढ़ी और महिला प्लेटफार्म पर आने के बजाय पटरी में चली गई। इस दौरान मचाए गए शोर को सुनकर यात्रियों ने इमरजेंसी चैन को खींचा, जिससे ट्रेन रूक गई, लेकिन महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। रेलवे के कर्मचारियों के सहयोग से महिला को बैकुंठपुर जिला अस्पताल लेकर स्वजन पहुंचे। यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया था, यहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह 5.30 बजे उसकी मौत हो गई। घटना से स्वजन में शोक का माहौल है। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

कोटवारी भूमि प्रकरण एक माह में निराकृत कर शासन के खाते में दर्ज करें

कलेक्टर ने अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई और डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता पर जोर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामले आमजन के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े होते हैं, अत: सभी अधिकारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से कोटवारी भूमि के हस्तांतरण एवं क्रय-विक्रय प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही यह परीक्षण भी सुनिश्चित करें कि किन प्रकरणों में एक बार तथा किन मामलों में एक से अधिक बार हस्तांतरण हुआ है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोटवारी भूमि से संबंधित सभी लंबित प्रकरण एक माह के भीतर पूर्ण कर कोटवारी भूमि को शासन के खाते में दर्ज किया जाए, संबंधित भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करते हुए उसकी खरीदी-बिक्री पर रोक सुनिश्चित की जाए। पट्टे से प्राप्त भूमि की अद्यतन जानकारी आगामी समय-सीमा बैठक में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अवैध भूमि अतिक्रमण एवं कब्जे के प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, खाता विभाजन तथा भू-अर्जन प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति लाने पर बल दिया विशेष रूप से विवादित एवं अविवादित बंटवारे के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील नायक, अमृतलाल ध्रुव सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता

कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने-अपने न्यायालयों में सुनवाई हेतु निश्चित दिवस निर्धारित करने तथा सभी प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड संधारण से पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को सुविधा मिलेगी। मतदाता सूची के एसआईआर कार्य एवं त्रुटि सुधार आवेदनों का भी समय-सीमा में निराकरण करने को कहा गया। आगामी समीक्षा बैठक तक डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

मैदानी अमले की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें

प्राकृतिक आपदा सहायता प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि संबंधित पटवारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर मौका-मुआयना करें, आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर शीघ्र जिला कार्यालय प्रेषित करें। वृक्ष कटाई से संबंधित प्रकरणों में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कर शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने को कहा गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए मैदानी अमला लक्ष्य निर्धारित कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करे। कलेक्टर ने नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, किसान किताब वितरण, आधार सीडिंग तथा वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में नियमित मॉनिटरिंग करने एवं प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

भृत्य के नहीं रहने से राजस्व नकल की प्राप्ति के आवेदन धूल खा रहे

करीब तीन माह से तहसील के कानूनगो शाखा की व्यवस्था ध्वस्त

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के तहसील कार्यालय में स्थित कानूनगो शाखा में भृत्य के स्थानांतरण के बाद करीब ढाई-तीन माह से कार्यालय का काम ठप है। कार्यालय के कानूनगो सहायक ग्रेड-2 को छोटे-छोटे कामों के लिए दौड़ लगाना पड़ रहा है। नकल संबंधित दस्तावेजों के लिए रोजाना लोग कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और उल्टे पांव वापस लौट रहे हैं। एकमात्र भृत्य के नहीं रहने से यहां की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे में सैकड़ों आवेदन कानूनगो शाखा में पेंडिंग हैं। नकल से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने से राजस्व प्रकरणों को निपटाने में भी विलंब की स्थिति बन रही है। इसकी पुष्टि स्वयं तहसीलदार भी कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक तहसील कार्यालय के कानूनगो शाखा में भृत्य के पद पर विनोद कुशवाहा पदस्थ थे, जिनका स्थानांतरण बीते वर्ष दिसम्बर माह में ही कलेक्टोरेट के दूसरी शाखा में हो गया है। करीब तीन माह होने को हैं, इस कार्यालय में भृत्य की पदस्थापना नहीं हो पाई है, ऐसे में इस कार्यालय में एकमात्र कानूनगो श्रीमती केतन गुप्ता सहायक ग्रेड-2 के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ गई है। एक पटवारी, कोटवार को यहां अटैचमेंट में बैठाया गया है, लेकिन इन्हें काम की जानकारी का अभाव है और आवश्यक कार्यों के लिए कानूनगो को ही चक्कर काटना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी स्वीकारते हैं कि कानूनगो शाखा में कर्मचारी का टोंटा है। स्थानांतरण के पहले उक्त भृत्य ही रिकार्ड रूम से नकल निकालने का काम करता था। इसके जाने के बाद से राजस्व नकल से संबंधित सारे आवेदन धूल खा रहे हैं। नकल की प्राप्ति के लिए चक्कर काटने की नौबत बन रही है। सहायक ग्रेड-2 के द्वारा भृत्य के स्थानांतरण के बाद से होने वाली दिक्कतों से तहसीलदार को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कानूनगो का कहना है कि रिकार्ड रूम की चाबी किसी को भी सौंपा नहीं जा सकता है। अगर राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्हें कोटवारों, पटवारी का सहयोग लेने कहा गया, लेकिन रिकार्ड रूम में रखे गए रिकार्डों की जानकारी इन्हें नहीं होने से काफी दिक्कत हो रही है।

नकल के 200 से अधिक आवेदन पेंडिंग

आफिस कानूनगो श्रीमती केतन गुप्ता ने औपचारिक बातचीत में हो रही दिक्कतों को साझा किया और बताया कि वर्तमान में 200 से अधिक नकल से संबंधित आवेदन पेंडिंग हैं। भृत्य के जाने के बाद से रिकार्ड रूम से संबंधित काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरा ऐसा कोई नियमित स्टाफ अभी तक नहीं मिला है, जिसे रिकार्ड रूम की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जिम्मेदारी भरा काम होने के कारण यहां की चाबी किसी भी कर्मचारी को सौंप देना संभव नहीं है।

मैंने कलेक्टर, एसडीएम को दी है जानकारी-तहसीलदार

तहसीलदार उमेश्वर सिंह बाज ने बताया कि कानूनगो शाखा में पूर्व में पदस्थ भृत्य जिला कार्यालय में अटैच है, इसके बाद कर्मचारी का अभाव बना हुआ है। इससे कलेक्टर व एसडीएम को अवगत कराया गया है। पटवारी, कोटवार को कानूनगो शाखा में अटैच किया गया है, लेकिन नकल से संबंधित कार्य किसी जिम्मेदार से ही कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तहसील में 03 न्यायालय और छह शाखाओं का संचालन हो रहा है। यहां कम से कम 4-5 भृत्य की आवश्यकता है। कानूनगो शाखा का रिकार्ड रूम, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के ऊपर है। नकल से संबंधित आवेदन मिलने पर भृत्य यहां से रिकार्ड लेकर आता था, जिसे आवेदकों को उपलब्ध कराया जाता था। उन्होंने स्वीकार किया कि एकमात्र भृत्य के कारण राजस्व नकल से संबंधित काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

जीवन दीप समिति व छोटे पांव मजबूत कदम के शिविर में 59 बने रक्तवीर

छ.ग.फ्रंटलाइन जरही। दूसरों को जीवन देने की भावना के साथ 59 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन छोटे पांव मजबूत कदम और जीवन दीप समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर में रक्तदाताओं को 'रक्तवीर सम्मान' से सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा आयोजित यह दूसरा रक्तदान शिविर था। रक्तदान को लेकर युवाओं और महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। दस से अधिक बार रक्तदान करने वाले नियमित दाताओं तथा महिला रक्तदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अभियोजन अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी चंदौरा मनोज कुमार सिंह, मुकेश गर्ग, नीलम रजक सहित अन्य अतिथियों ने छत्तीसगढ़ी महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की।

शिविर में पहुंचे सूरजपुर जिले के सीएमएचओ डॉ. कपिल पैंकरा ने रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि नियमित रक्तदान से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अभियोजन अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रक्तदान करना और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना दोनों ही पुण्य कार्य हैं। थाना प्रभारी मनोज सिंह ने स्वयं रक्तदान करते हुए कहा कि ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराने के लिए ऐसे शिविर बेहद जरूरी हैं। संस्था के संयोजक राकेश मित्तल ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल रक्त संग्रह करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को भयमुक्त करना है।

पिता-पुत्र और पति-पत्नी ने भी दिखाई भागीदारी

शिविर में नगर के व्यापारी मुकेश गर्ग ने अपने पुत्र संस्कार गर्ग के साथ रक्तदान किया। पुलिस विभाग के विवेक पांडेय और उनकी पत्नी लक्ष्मी पांडे, प्रमोद नाविक और उनकी पत्नी आंचल नाविक ने भी रक्तदान किया। लक्ष्मी पांडे और आंचल नाविक का यह पहला रक्तदान था, जिसे उन्होंने प्रेरणादायक अनुभव बताया। इसी प्रकार एक ही परिवार के तीन सदस्यों अनिल मित्तल, अमित मित्तल और अंकित मित्तल ने भी रक्तदान कर समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। थाना प्रभारी मनोज सिंह, प्रधान आरक्षक अवधेश कुशवाहा, विवेक पांडे, शिक्षक शेखर यादव, आईटीआई के दिनेश पटेल, स्वास्थ्य विभाग के राजेश वर्मा, कृषि महाविद्यालय के डॉ. उमेश जायसवाल, डॉ. चेनेश पटेल, डॉ. रोमिला खेश, सहायक प्राध्यापक अंकुश केरकेट्टा और पीटीआई आकाश सिंह राजपूत सहित कई लोगों ने रक्तदान किया।

अचेत हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम पलढ़ा निवासी कनीलाल लकड़ा पिता नानसाय लकड़ा 38 वर्ष की संदेहास्पद स्थिति में पुलिया के पास अचेत अवस्था में मिला, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक 15 फरवरी को शिवपुर मेला देखने के लिए मोटरसायकल से अकेले निकला था, लेकिन रात में घर नहीं लौटा। स्वजन जब खोजबीन के लिए निकले, तो घर के करीब स्थित छोटे पुलिया के पास बाइक क्षतिग्रस्त हाल में मिला और युवक बेहोशी की हालत में पड़ा था। स्वजन उसे प्रतापपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराए थे, यहां शाम 7.50 बजे वह दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

कोल्ड स्टोर से बड़ी मात्रा में कालातीत बीज जप्त

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महामाया कोल्ड स्टोर से बड़ी मात्रा में कालातीत बीज जप्त किया है। किसानों की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी कोल्ड स्टोर पहुंचे, और कालातीत बीज किसानों को खपाने की साजिश की सच्चाई उजागर हुई। यहां धान, मक्का, सरसों बीज का भंडारण किया गया था, इनमें कई नामी कंपनियो के बीज थे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर